

राष्ट्रपति अभिभाषण : सरकारी विज्ञापन

- ♦ ykyÑ".k vkMok.kh
- ♦ MkW ejyh eukgj tks'kh
- ♦ , e- oad\$ k uk; Mw
- ♦ 'kkark dpekj



Hkkj rh; turk i kVhZ

प्रकाशकीय

महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने गत 22 फरवरी को संसद के बजट-सत्र में दोनों सदन की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। तत्पश्चात् राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुआ। धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में तीन दिन चर्चा हुई। चर्चा के दौरान लोकसभा में भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी एवं डॉ. मुरली मनोहर जोशी तथा राज्यसभा में श्री वेंकैया नायडू एवं श्री शांता कुमार आदि भाजपा सांसदों ने अपने तर्कों व तथ्यों के बूते संप्रग सरकार की गलत नीतियों की कड़ी आलोचना की। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने राष्ट्रपति अभिभाषण को सरकारी विज्ञापन सरीखा करार दिया, जिसमें सरकारी कार्यक्रमों व उपलब्धियों का संकलन होता है। भाजपा सांसदों ने कहा कि देश आज कई चुनौतियों का सामना कर रहा है लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में उनसे निपटने के उपायों की दिशा का स्पष्ट अभाव है।

हम यहां संसद में 'राष्ट्रपति अभिभाषण' पर हुई चर्चा के दौरान भाजपा सांसदों द्वारा दिए गए भाषणों का संपादित पाठ प्रकाशित कर रहे हैं जिससे संप्रग सरकार के झूठे वादों की पोल खुल सके।

ekp] 2010

i xdk' kd
Hkkj rh; turk i kVhZ
11] v' kksd j kM]
ubZ fnYyh&110001

कश्मीर पर गुप्त समझौता न करें यूपीए सरकार

& ykyN".k vkMok.kh

सभापति जी, मैंने जो बात कही, मैं उसका उदाहरण देता हूँ। मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में अग्नि-3 का उल्लेख है। अग्नि-3 का उल्लेख करते हुए उसकी प्रशंसा की गयी है। अग्नि-3 का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक हुआ और इस पर राष्ट्रपति ने जो प्रसन्नता प्रगट की, मैं उसका स्वागत करता हूँ। यह खुशी की बात है। मैं बधाई देता हूँ हमारे जिन वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स ने उसको करके दिखाया, मैं उसमें यह जोड़ना चाहूंगा कि जहां हमारी सेना कई मामलों में इतना आगे बढ़ रही है, वहां अभी भी हमारी सेना की काफी डिफेंडेंस विदेशी शस्त्रास्त्रों पर है। उसमें स्वदेशीकरण स्वालंबन हम जितना ला सकें, प्रयत्नपूर्वक उसे लाने की दिशा में मजबूत कदम उठाने चाहिए। मेरी मान्यता है कि जैसे वर्ष 1990-91 में हमने एक मौलिक परिवर्तन किया तो आज भी प्राइवेट सैक्टर को डिफेंस के क्षेत्र में भी इन्वाल्व करना चाहिए। अभी भी होता है, लेकिन अभी जो होता है वह केवल प्रोडक्शन में होता है, शोध में नहीं होता है। हम डीआरडीओ पर रिसर्च के लिए अवलंबित रहते हैं। जरूरत इस बात की है कि दुनिया के देशों के साथ, जिनके साथ हमको टक्कर लेनी है, मुकाबला करना है, वहां पर सफलता तब मिलती है जब पूरे देश को इस कार्य में इन्वॉल्व किया जाता है। हमारे यहां पर भी लोग हैं जो वह कर सकते हैं और उन्हें इन्वॉल्व करना चाहिए और कोशिश यह होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी हम जितने स्वावलम्बी हो सकें, उतने हों। काफी दूर है वह दृश्य। मेरे पास स्टेटिस्टिक्स हैं कि हम कितनी परसेंटेज में उन पर अवलम्बित हैं। वह काफी बड़ा है, लेकिन इस दिशा में ईमानदारी से, प्रामाणिकता से और तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। मैं इस बात का स्वागत करता हूँ कि इस दृष्टि से वित्त मंत्रालय ने डिफेंस मिनिस्टर को अधिकार दिया है कि एक हजार करोड़ रुपये के डिफेंस प्रोजेक्ट्स के लिए वे स्वयं निर्णय कर सकते हैं। उसके लिए कैबिनेट कमेटी

आन सिक्युरिटी के पास जाना जरूरी नहीं है। यह जो निर्णय है, यह सही दिशा में है। लेकिन यह निर्णय होने के बाद भी मैं कहूंगा, वित्त मंत्री जी यहां नहीं हैं और डिफेंस मिनिस्टर भी नहीं हैं, कि उसके कारण पारदर्शिता और एकाउंटेबिलिटी डाइलूट नहीं होनी चाहिए। वह सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन हां, इनडिजिनाइजेशन जरूरी है, जरूरी करना चाहिए। इसी संदर्भ में मैं स्मरण करता हूँ कि पिछले साल काफी आंदोलन हुआ था और रक्षा मंत्रालय के बहुत सारे लोग इस बात पर आग्रही थे। 22 हजार सम्मान पदक जो उन्हें मिले थे, उनमें अधिकारी भी थे, जवान भी थे, वे उन्होंने लौटा दिए। अभियान इस रूप का चला कि हमारे यहां पर वन रैंक वन पेंशन होनी चाहिए और इसके लिए आग्रह किया। मुझे स्वयं याद है कि मैं भी उनके यहां गया था, उनका समर्थन किया था। उसके बाद मुझे स्मरण है कि प्रधान मंत्री जी ने स्वयं भाषण दिया था जिसमें उन्होंने लाल किले से कहा था कि कैबिनेट सैक्रेटरी के नेतृत्व में जो कमेटी बनी है, उस कमेटी की सिफारिशें हमने स्वीकार की हैं। इतना ही नहीं, मुझे याद है कि वित्त मंत्री ने एमाउंट भी बताया था और कहा कि हमने न केवल उन्हें स्वीकार की हैं, लेकिन उसके कारण हमें प्रति वर्ष 2,100 करोड़ रुपये उनकी पेंशन पर खर्च करने पड़ेंगे। इन्हीं दिनों में मुझसे कई प्रमुख एक्स सर्विसमैन का मिलना हुआ, जिन्होंने कहा कि दोनों की घोषणा के बाद, प्रधान मंत्री जी की घोषणा और वित्त मंत्री जी की घोषणा, वित्त मंत्री जी की घोषणा उनके 2009 की बजट स्पीच का हिस्सा था। उसके बाद भी यह काम नहीं हुआ है। कोई कठिनाइयां होंगी, मैं नहीं जानता, वे बताएंगे। लेकिन मुझे लगा कि मेरी ड्यूटी है कि मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाऊँ, क्योंकि स्वयं राष्ट्रपति के अभिभाषण में उसका उल्लेख है। उन्होंने कहा है कि हमने एक्स सर्विसमैन की पेंशन डिमांड्स के बारे में एक व्यवस्था बनाई है। वन रैंक वन पेंशन का उल्लेख नहीं है, केवल मात्र यह कहा है कि हम उसकी एक व्यवस्था कर रहे हैं कि उन्हें पेंशन की कोई शिकायत न हो। मैं चाहूंगा कि इस बारे में स्पष्टीकरण हो, क्योंकि उनको नाराजगी है। यहां तक कि मुझे कल कुछ लोगों ने कहा कि हम फिर से अभियान करेंगे, कैम्पेन करेंगे। मैं समझता हूँ कि आज जवान और सेना के अधिकारी को फिर से इस प्रकार की शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, खास करके जब कैटेगॉरिकली प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री, दोनों ने कह दिया। चुनाव से पहले तो यह कहा था कि हमने कैबिनेट सैक्रेटरी के नेतृत्व में एक कमेटी इसे एग्जामिन करने के लिए बनायी है। ...

प्रधान मंत्री जी, आपने कोई फिगर्स की बात नहीं की थी। आपने केवल यही कहा था कि कैबिनेट सैक्रेट्री के नेतृत्व में जो कमेटी बनी है, उसे हमने स्वीकार किया है और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में स्पेसीफिकली कहा और यह कहा कि 2100 करोड़ रुपये प्रति वर्ष हमारा खर्च बढ़ेगा, लेकिन हमने स्वीकार किया है। I am told that it has not been implemented, it has not been done. This is the problem. It is, therefore, that those who met me told me that they would be forced once again to take recourse to the same thing. This should not happen. This is my plea.

I am not creating a rift. I am simply saying, I am conveying their feelings. And I am saying that earlier also when you did this and the Finance Minister made that statement, he must have made it with due responsibility. He said it in his Budget speech. And yet if it has not been implemented, it is a matter of concern. Well, if it has been implemented, I am very happy. But I can tell you that this is not the feeling that I got from the ex-servicemen. Therefore, I thought it my duty to convey it to you and to the House. प्रधान मंत्री जी एक विषय और है। मुझे याद है कि इस विषय पर मार्च 2009 में, मैंने पार्टी की ओर से यह सवाल उठाया था कि हिन्दुस्तान में हमें संसाधनों की आवश्यकता है। हम संसाधन कहां से लायें, क्योंकि देश की गरीबी खत्म करने के लिए, पिछड़ापन खत्म करने के लिए, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, इन्फ्रास्ट्रक्चर फुली डेवलप करने के लिए हमें काफी खर्चा चाहिए। मैं वर्षों से सुनता आया हूँ, जब से मैं संसद में आया कि हिन्दुस्तान में कितनी ब्लैकमनी है, कितना काला धन है और वह काला धन विदेशी बैंकों में जाकर जमा होता है। मुझे याद है कि मैंने जब वक्तव्य दिया था तब मैंने कहा था कि विदेश में बहुत सारे सशक्त देश जैसे जर्मनी, अमेरिका वगैरह आज आर्थिक संकट में हैं। इसलिए उन्होंने अभियान चलाया है कि स्विस बैंक्स और टैक्स हैवेन्स में जो गोपनीयता है जिसका लाभ उठाकर बहुत भ्रष्ट तरीके से धन कमाने वाले या टैक्स इवेजन करके धन कमाने वाले वहां पैसा जमा कराते हैं, उनके ऊपर दबाव जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों से पड़ रहा है। उसका परिणाम भी निकल रहा है। अच्छा होगा कि भारत इसमें रूचि ले और हमारा जो धन विदेशों में है, उसको वापस लाने के लिए प्रयत्न करे। संसद को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति जी ने उसका उल्लेख किया है। पहली बार

उल्लेख हुआ है इस धन का। मुझे खुशी है, मैं इसका स्वागत करता हूँ, लेकिन मुझे जानकारी नहीं है कि प्रगति कितनी हुई है? जिक्र हुआ है कि हमने अपना कानून अमेंड किया है, कुछ देशों से निगोशिएट कर रहे हैं कि वे हमारे साथ एग्रीमेंट्स करें, जिनके साथ हमारे एग्रीमेंट्स हैं, उनको रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मेरी बात को एंडोर्स करते हुए कहा कि हमारी सरकार करेगी इस काम को। प्रधानमंत्री जी, मैं इस बात का स्वागत करता हूँ कि आपने उसको नोटिस करके कहा कि हम करेंगे और आप उस दिशा में लगे हैं, जिसका उल्लेख राष्ट्रपति के अभिभाषण में है कि हमने ये-ये काम किए हैं जैसे लॉ अमेंड किया है। मैं मांग करता हूँ कि इस पर एक स्टेटस पेपर या श्वेत पत्र सदन के सामने लाया जाए कि अब तक प्रगति क्या हुई है। यह बजट के समय भी आ सकता है। किस-किस से क्या वार्ता हो रही है? क्या यह बात सही है कि 50 नाम हमको Liechtenstein से मिले हैं? क्या नाम हैं, कौन-कौन लोग हैं? कितना धन है? क्या यह सही है कि जिस प्रकार की व्यवस्था अमेरिका करवा सकती है, जर्मनी करवा सकती है, हम नहीं करवा पा रहे हैं? हमें वैसा सहयोग नहीं मिल पा रहा है? क्या सही बात है? इस मामले में सदन को जितना विश्वास में लिया जाएगा, उतना ही सरकार को इस मामले में ज्यादा ताकत मिलेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि बहुत अच्छी बात है कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में आप इस बात को ले आए हैं, आगे के लिए रास्ता खुला है, सदन भी उसकी मांग करे कि क्या हुआ। उस दिन, आज भी देखा होगा, पिछले पांच-सात दिनों में देखा होगा कि देश में अगर कोई चर्चा, चिंता किसी बात की लोगों में अधिक है, तो वह महंगाई है। मैं यहां था जब सुषमा जी बोली थीं और पूरे सदन में उनकी बात सुनी थी। महंगाई जितनी मात्रा में कुप्रबंध के कारण है, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसका इलाज आप करेंगे। लोगों में इतना गुस्सा है, इतनी नाराजगी है। लेकिन उन्होंने चार और बातें कही थीं, उसका उत्तर मंत्री जी के जवाब में नहीं मिला। ये चार स्कैम्स हैं जिनके कारण ऐसा हुआ। यह केवल कुप्रबंध की वजह से नहीं है, केवल मिसमैनेजमेंट ऑफ दि इकोनोमी नहीं है, it is also scandals relating to export and import. उन चार स्कैम्स के बारे में उनकी मांग थी कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी बनाई जाए। इसलिए इस मुद्दे पर एक जेपीसी बनाई जानी चाहिए। लेकिन उसका उत्तर नहीं आया। मैं समझता हूँ कि अगर सरकार इंटरस्टेड है करप्शन को रोकने में, अगर सरकार वास्तव में

महंगाई को रोकना चाहती है तो केवल मात्र प्रबंधन ठीक होना ही पर्याप्त नहीं है। यह जो समय-समय पर लोग करपान करके निकल जाते हैं, बच जाते हैं, स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार होता है, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। यह नहीं होना चाहिए। प्रधान मंत्री जी से अपेक्षा है कि वह इस मामले में कदम उठाएंगे। इसीलिए मैं फिर दोहराता हूँ कि उस दिन सुषमाजी ने जो जेपीसी गठित करने की मांग की थी, जिसकी अन्य सदस्यों ने भी पुष्टि की थी, वह बननी चाहिए। राव इन्द्रजीत सिंह जी ने स्वाभाविक रूप से सरकार की प्रशंसा की कि सरकार ने यह किया, वह किया, बहुत अच्छा है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले चुनावों में जितनी सफलता सरकार को मिली उसका प्रमुख कारण था कि हमने किसानों को राहत दी। जिस साल यानी 2008 में सरकार ने यह राहत दी, उस साल, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार, 16196 किसानों ने आत्महत्या की। यह उस साल की रिपोर्ट है।

It is not. It is that year only and not only that year, but mainly in Maharashtra and Andhra. 16,196 farmers committed suicide in the year 2008. Maybe, because most of those who commit suicide are those who do not take loans from banks. आपके उस प्रावधान का यह नतीजा हुआ कि बैंकों को अपने बैलेंस अकाउंट ठीक करने का मौका तो मिल गया, लेकिन किसानों को राहत नहीं मिली। किसानों को राहत देने के लिए मुझे इसमें दो ही बातें महत्वपूर्ण लगीं। राव इन्द्रजीत सिंह जी ने जो बातें कहीं, उनमें कई तो मेरी समझ में नहीं आईं कि कहां से कहीं। एक माननीय सदस्य: किसी की समझ में नहीं आईं। उन्होंने सरकार का सबसे बड़ा जो पाइंट बताया, वह लोन वेवर्स का बताया। दूसरा उन्होंने जो जिक्र किया, उसका मैं स्वागत करता हूँ, वह पेड न्यूज़ का जिक्र उन्होंने किया। अब उस पर बात चली है, यह एक गम्भीर मुद्दा है। मेरी इस मामले में चुनाव आयोग से भी बात हुई है। मैंने कहा है कि हर कैंडिडेट का खर्चा आप मॉनिटर कर सकते हैं चुनाव के समय, तो चुनाव के समय जो पत्र-पत्रिकाएं हैं, टेलीविजन के चैनल्स हैं, उन्हें कितना रुपया प्राप्त होता है और कहां-कहां से प्राप्त होता है, लेजिटीमेट एडवर्टाइजमेंट्स से कितना प्राप्त होता है, इस प्रकार पेड न्यूज़ के रूप में कैंडिडेट्स से या पार्टीज से कितना एक्सटोल करते हैं, इसका हिसाब भी रखना चाहिए। सन् 1970 में मैं पहली बार संसद में चुनकर आया। तब से लेकर आज तक अगर किसी एक विषय पर मैं लगातार व्यक्तिगत रूप से जोर देता हूँ तो वह चुनाव सुधार के संदर्भ में है।

मुझे याद है कि सन् 1970 में वाजपेयी जी लोक सभा में थे और मैं राज्य सभा में था। उस समय चुनाव सुधारों पर पहली कमेटी बनी थी और जगन्नाथ राव जी उस समिति के अध्यक्ष थे। शायद अब वह नहीं रहे। उस समिति में लोक सभा की ओर से वाजपेयी जी और राज्य सभा की ओर से मैं अपनी पार्टी के सदस्य थे। बहुत सिफारिशें कीं, अच्छी कीं, कई इम्प्लीमेंट हुईं, कई नहीं हुईं, लेकिन एक सिफारिश थी और वह यह थी कि जहां तक संभव हो चुनाव का खर्चा शासन को वहन करना चाहिए। आज जो खर्चा प्रत्याशी को या पार्टी को करना पड़ता है, धीरे-धीरे शासन पर ट्रांसफर होना चाहिये। प्रधान मंत्री जी, उसके बाद इंद्रजीत गुप्ता की कमेटी बनी थी, उसके बाद दिनेश गोस्वामी कमेटी बनी, तारकुंडे कमेटी जयप्रकाश नारायण जी ने बनाई थी, उसमें भी मैं बोला था। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यह जो पेड-न्यूज़ का मामला आया है यह एक एडीशनल प्रॉब्लम करपान का बन गया है। माननीय प्रधान मंत्री जी, एक बार आपसे भी बात हुई थी कि 6 साल जब हम सरकार में थे तो यह बात हमें बहुत खटकती थी कि हर दो साल बाद जनरल इलेक्शन होता है या मिनी जनरल इलेक्शन होता है। उसका कारण है कि पहले चार इलेक्शन्स 1952, 1957, 1962, 1967 लोक सभा और विधान सभाओं के चुनाव साथ-साथ हुए थे। सन् 1971 के बाद से आज तक लोक सभा अलग, विधान सभा अलग और परिणाम यह है कि शासन में बैठे लोगों को यदि कोई निर्णय करना होता था और लगता था कि यह निर्णय जल्दी होना चाहिए, तो कहा जाता था कि अमुक स्थान पर इलेक्शन होना है, वह निकल जाए तो काम करना। इस कारण बहुत नुकसान शासन का होता था और बहुत नुकसान समाज-व्यवस्था का होता है और बहुत नुकसान होता है और कितने ही मामलों में। मैं चाहूंगा कि इस पर फिर से विचार होना चाहिए कि हिंदुस्तान में लोक सभा और विधान सभा के चुनाव हर पांच साल बाद एक साथ हों। इसका कोई साधारण तरीका नहीं होगा बल्कि संविधान में अमेंडमेंट हमें करना होगा। यूरोप की अधिकांश डेमोक्रेसीज में चुनाव एक साथ होता है और बीच में चुनाव नहीं होता है। हाउस डिजोल्व नहीं होता है। पांच साल में या जितना भी टर्म है तीन-तीन सरकारें तो हो सकती हैं लेकिन चुनाव एक साथ ही होता है। हमें भी इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। यूके का उदाहरण हमने लिया है लेकिन हिंदुस्तान में समस्या यह है कि यूके में तो मात्र एक वहां की हाउस ऑफ कॉमन्स है, हमारे यहां पर न केवल लोक सभा है बल्कि 28 विधान सभाएं हैं और 28

विधान सभाएं और एक लोक सभा, इन सभी का चुनाव एक साथ हो तो उसका शासन को भी लाभ होगा, राजनीति को भी लाभ होगा और खर्चा कम होगा। ये कुछ चीजें हैं जिन पर मैं बल देना चाहूंगा कि इनका इलाज करना चाहिए।

मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर आता हूँ और वह यह है कि शर्मिल-शेख में माननीय प्रधान मंत्री ने जब घोषणा की थी कि वहां के प्रधान मंत्री ने मिलकर कहा था कि हम टैरर एंड टॉक्स, आतंकवाद और वार्ता को हम एक साथ नहीं जोड़ते हैं और हमारे पाकिस्तान के मित्र बहुत खुश हुए थे। मैं जानता हूँ कि जब आगरा में जनरल मुशर्रफ के साथ माननीय वाजपेयी जी की वार्ता हुई थी और बिना किसी समझौते के उन्हें वापस जाना पड़ा था तो वह बहुत नाराज हुआ था।

मैं मानता हूँ कि उस निर्णय के कारण ही तीन साल बाद वर्ष 2004 में जनरल मुशर्रफ ने सार्वजनिक रूप से कहा, जिस बात को वे आगरा वार्ता में मानने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने कहा कि हमारा यहां के आतंकवाद से कोई लेना-देना नहीं है। आज अगर जम्मू-कश्मीर में बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, तो उसका कारण है कि वे लोग अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं और इस कारण वे मारे जाते हैं। उन्होंने यह स्टैंड लिया। लेकिन वर्ष 2004 में सार्क की मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के साथ उन्होंने अपना स्टैंड बदला और कहा कि मैं वचन देता हूँ कि पाकिस्तान या पाकिस्तान के हाथ में कोई भी भूमि, जिसका मतलब था पाक अधिकृत कश्मीर, पीओके, इसका उपयोग मैं भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए नहीं होने दूंगा। मैं मानता हूँ कि आगरा में जो स्टैंड लिया था, उसका परिणाम था कि इस्लामाबाद में उन्होंने सही स्टैंड लिया। मेरा प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि आपने वहां के पहले प्रधानमंत्री के साथ जो निर्णय लिया, जो कि 26/11 के बाद लगा कि आप उसे बदल रहे हैं और 26/11 के बाद आपका पुराना स्टेटमेंट जो शर्म-अल-शेख का था, उसकी कमी आपको नज़र आती है। अचानक अभी फिर जो हुआ, उससे मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि आखिर यह क्यों हुआ। यह नहीं होना चाहिए था, जबकि 26/11 के मामले में स्वयं गृह मंत्री लगातार कहते रहे कि उनका रवैया सही नहीं है। हम उन्हें जितने डोजियर देते जा रहे हैं, वह उनको कहते हैं कि यह तो लिट्रेचर है, यह कोई ऐविडेंस नहीं है। अनेक बार उन्होंने स्टेटमेंट दी है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन लगता है कि शायद सरकार भी इस बारे में एकमत नहीं

है। सरकार एकमत हो या न हो, देश बहुत चिंतित है। खासकर पिछले दिनों जब मैंने एक लम्बा लेख अमेरिकन अखबार में पढ़ा। उनकी एक नई थीसिस है और उसका जो समिंगअप है, वह यह है कि "That the road to peace in Kabul goes through Kashmir." यह न्यूज़वीक अखबार का हैडिंग है। मैं सारा कोट नहीं करता, लेकिन हमें यह भी भाव मिलता है, जैसे मानो किसी स्टेज पर हम इस बात के लिए तैयार हो गए। मैं न्यूज़वीक को कोट कर रहा हूँ— "Sometime in the last year secret back channel talks between India and Pakistan over Kashmir re-started; say US and Indian sources." This is the Newsweek Report. "The countries were reportedly on the verge of a breakthrough when Musharraf was ousted in August 2008. Then the Mumbai terror attacks in November badly frayed relations. For negotiations to resume now would represent a huge boon for the region." यह उनके अखबार ने लिखा है। "The pay-off would stretch all the way to Washington. Peace between India and Pakistan could help unlock another conflict with even higher stakes for the United States; the war in Afghanistan. Indeed a growing chorus of experts has begun arguing that the road to Kabul runs through Kashmir; that the US will never stabilise the former without peace in the latter. Suddenly bringing India and Pakistan together seems to be very much in America's interest." Bringing India and Pakistan together is in our interest also. हम उनके विरुद्ध नहीं हैं, आखिर हम पड़ोसी हैं। पड़ोसी होते हुए भी, यह पड़ोसी वाली बात अभी-अभी श्री एस.एम. कृष्णा ने कही कि can we forget that we are neighbour. No, we cannot forget. हम अपना इतिहास तो बदल सकते हैं लेकिन भूगोल नहीं बदल सकते, जियोग्राफी नहीं बदल सकते। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि यह भी जियोग्राफी ही है कि वे हमारे पड़ोसी हैं इसलिए क्रास बार्डर टेररिज्म होता है। हम इसे भी भूल नहीं सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हम देश का इन्ट्रस्ट सबसे पहले देखें। भारत और पाकिस्तान मित्र बनें, उनका सौहार्द हो, हम सभी चाहेंगे, हर कोई चाहता है। उनको जिस समय आगरा में निमंत्रण दिया था उससे पहले कारगिल हुआ था फिर भी निमंत्रण दिया था क्योंकि हम चाहते थे मित्रता हो। लेकिन जब उन्होंने कहा कि आतंकवाद है ही नहीं, कोई बात ही नहीं है तब हमने कहा आप वापिस जाइए। जब उन्होंने माना

तब हमने उनकी बात मानी। और तो छोड़िए, पिछले दिनों हमारे अपने नेता क्या कहते हैं, सेना के प्रमुख क्या कहते हैं। मैंने 46 पेज लंबी रिपोर्ट पढ़ी है, यूएस इंटेलीजेंस कम्युनिटी डेनिस लेयर, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलीजेंस जिन्होंने सीनेट की सैलेक्ट कमेटी ऑन इंटेलीजेंस को रिपोर्ट दी है और उस रिपोर्ट में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम पाकिस्तान से उम्मीद करते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ हमारा साथ देगा, अमरीका का, तो हम गलतफहमी में न रहें। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का कहना है कि जो आतंकवादी आउटफिट्स पाकिस्तान के खिलाफ हैं, उन्हीं के खिलाफ हम एक्शन लेंगे, औरों से हमारा कोई सरोकार नहीं है, तालीबान का हम साथ ही देंगे। इतना ही नहीं आगे चलकर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है – "It is our conviction that an important part of its strategic arsenal to counter India's military and economic advantage will be these terrorist outfits." यह पाकिस्तान का विश्वास है, यह अमरीका की रिपोर्ट है। भारत के अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपनी जानकारी है कि इन्होंने बड़ी संख्या में आतंकवादी भारत में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए तैयार कर रखे हैं। ऐसी स्थिति में हमने वार्ता करके क्या पाया? श्री एस.एम. कृष्णा कह सकते हैं कि कन्सट्रक्टिव वार्ता थी। लेकिन उनके काउंटरपार्ट कहते हैं कि कास्मेटिक एंगेजमेंट हमें नहीं चाहिए, पाकिस्तान को नहीं चाहिए। Pakistan does not want to be lectured by India. मुझे स्वयं लगा कि हम अनावश्यक रूप से इन्सर्ज इन्वाइट कर रहे हैं, वे आकर इस प्रकार की भाषा हमसे बोलें। आज उनकी स्थिति कितनी खराब है कि वे कहें कि हम केवल मात्र उन्हीं आतंकवादियों के खिलाफ हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करना चाहते हैं, हम बाकी का उपयोग भारत की शस्त्रीय शक्ति का मुकाबला करने के लिए करेंगे। हम फिर भी उनसे वार्ता करने को तैयार हैं? कोई अर्थ नहीं है। इतना लंबा भाषण दिया, स्टेटमेंट दी, मैंने ध्यान से पढ़ा लेकिन इसमें एक भी पोजीटिव चीज नहीं निकली, Except that, at least, there had been an agreement to keep in touch. कीप इन टच तो हमेशा है। जब उन्होंने 26. 11.2008 को मुम्बई में इतना बड़ा हमला किया, इतने लोगों को मार दिया तब भी We were in touch throughout. So keep in touch is not an achievement. मैं खास तौर से निवेदन करूंगा, Secret back channel talks between India and Pakistan over Kashmir. इसके बारे में सदन को विश्वास में लीजिए। क्या बातचीत हुई? इन दोनों में कभी-कभी एटोनोमी

के नाम पर गोइंग बैक टू प्री 1953 की चर्चा भी सुनते हैं, मैं नहीं जानता। हमारे समय में भी उन्होंने एक बार यह प्रस्ताव पास किया था। वहां जो सरकार थी, उन्होंने प्रस्ताव पास किया था। हमने कहा कि हम नहीं मान सकते। मैंने प्री 1953 कश्मीर देखा है, परमिट लेकर अंदर जाना पड़ता था। मैंने प्री 1953 कश्मीर देखा है कि जहां तिरंगा झंडा लहराते हुए लोग मारे गये और उन मार्टायर्स को हमने वहां श्रद्धांजलि दी थी। प्री 1953 कश्मीर हमने देखा है जब राष्ट्रपति का कश्मीर पर अधिकार नहीं था।

प्री 1953 राष्ट्रपति का अधिकार नहीं था, वहां पर राष्ट्रपति शासन नहीं हो सकता था। प्री 1953 वहां पर सुप्रीम कोर्ट का अधिकार नहीं था।

महोदय, मैं स्वीकार करता हूँ कि यह विषय मेरे लिए बहुत गंभीर है और मुझे लगता है कि अभी जिस दिशा में सरकार चल रही है, उसमें अगर कोई ऐसा गोपनीय समझौता कश्मीर के बारे में होने जा रहा है तो उसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे। वर्ष 1994 में इस सदन ने कश्मीर के बारे में जो सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया है, उसे न सदन भूल सकता है और न ही देश भूल सकता है। एक तरफ तो आप उस प्रस्ताव को ध्यान में रखिए और दूसरी तरफ India's Army Chief, General Deepak Kapur recently revealed that some 700 militants from Pakistan were waiting to infiltrate across the line of control in Jammu and Kashmir. General Kapur added that terror infrastructure across the line of control is very much intact and all-out efforts are being made to push inside as many infiltrators as possible. The Foreign Secretary, Nirupama Rao said: "We have to face hostile forces across our borders with Pakistan." इसीलिए बाकी सब बातों की उपेक्षा करने के बाद भी मैं चाहूंगा कि हमारा जो सर्वसम्मत प्रस्ताव है, जिसमें हमने कहा है कि "Jammu and Kashmir is, was and will always remain an integral part of India."

वे कहते हैं कि जम्मू-कश्मीर के जो पंडित हैं, उन्हें हम वापस नहीं ले जा सकते, उन्हें वहां नहीं बसा सकते और हम कहते हैं कि जो उधर चले गये, वहां जाकर आतंकवादी भी हो गये, उनका हम स्वागत करने जा रहे हैं। ये सारी बातें मन में चिंता पैदा करती हैं। इसीलिए मैं सावधान करना चाहता हूँ कि अगर इस दिशा में यह सरकार कोई कदम उठाएगी तो सारा देश उसके खिलाफ एक बहुत ही जबरदस्त आन्दोलन चलाएगा।

सभापति जी, मैं चाहूँगा कि कश्मीर के संबंध में अब तक ऑफिशियल या अनॉफिशियल जो भी वार्ता हुई है, प्रधान मंत्री जी अपने उत्तर में उसके बारे में पूरा खुलासा करेंगे। हम जानना चाहेंगे कि क्या बातचीत हुई है और किस दिशा में सारी चर्चा चली है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जब तक प्रैज़ीडेंट बुश वहाँ के राष्ट्रपति थे, तब तक इस विषय में अमरीका की नीति थी कि हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि वे कभी गलत काम नहीं करेंगे। मेरी जो समझ है, उसके अनुसार अमरीका के नए राष्ट्रपति ने अपने चुनाव के दौरान भी इस बात को बार बार कहा कि मैं अगर राष्ट्रपति बना तो मैं कश्मीर की समस्या को हल कराने के लिए पूरी ताकत लगाऊँगा, जबकि उससे पहले की अमरीका की नीति थी कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे जब तक भारत और पाकिस्तान दोनों नहीं कहेंगे। अगर दोनों नहीं कहेंगे तो हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि भारत और पाकिस्तान आपस में इसको हल करें।

I was on the statements. I have quoted them and I do not want to quote them now. But I would be happy if the hon. Prime Minister, who always speaks his mind, tells about the unanimous resolution regarding Kashmir passed by this Parliament. There can be no deviation from that. That is all. Therefore, it is that I expect you to tell us fully and frankly whatever has been discussed about Kashmir should be told in the House. I request with all seriousness that any dilution of India's sovereignty in Kashmir. I say this because it has been reported and very emphatically that the whole agreement was to come about when Mr. Musharraf was in the States. This is the latest buzz word. They are concerned very much about Afghanistan. They feel that from Afghanistan they would have a very bad defeat if something does not happen. Therefore, he says:

"We are keen to see that the road to Kabul goes through Kashmir." If there is no substance in it, I would be happy. All that I am saying is that if there is even an iota of truth in this kind of a thinking, then the country cannot be taken for granted; Parliament certainly cannot be taken for granted. Thank you, Sir.■

Synopsis

This is the only motion which is moved by the ruling side and does not face any opposition because it is the motion of thanks. The policies of the Government are criticized but the motion is not opposed and is passed unanimously. Sometimes we carry on with certain practices just because we have been following them for long but we need to ponder over the idea to modify them if the need arises. President's Address is prepared by the Cabinet hence it is expected that it would give credit to the Government rising above the party politics. Six years of Vajpayeeji's rule was marked by several achievements and this process is still continuing today. As far possible we should try to adopt an approach furthering mutual harmony. We are in Opposition and it is our duty to pinpoint shortcomings but this House needs to discuss as to how Government works, the institution and Government projects need to be named. The Presidents' Address has mentioned and applauded the AGNI-III. In this context, I would like to add that, even now, to a large extent, our defence forces depend upon foreign weapon systems. We should take concrete steps to bring about indigenisation in our weapon systems. We should involve private sector in our defence preparedness. I would like to welcome the instructions of the Ministry of Finance whereby it has authorized the Hon. Minister of Defence to take independent decisions with regard to the defence projects worth Rs.1,000 crore, but I would like to add that transparency and accountability should not be diluted on account of this.

In the last year a large number of service personnel had actively campaigned for one rank one pension. Subsequently, Hon. Prime Minister had announced from the ramparts of the Red Fort that the Government has accepted the recommendations made by the committee headed by the Cabinet Secretary. Not only this even the Minister of Finance had computed the expenditure on this item and had said that the Government will have to shell out approximately Rs.2,100 crore for their pension. The President's

Address has also mentioned that her Government has devised a system with regard to the pension demands of the Ex-servicemen. I would like to have categorical statement from the Government so that our jawans and officers should not have any grievance.

For years together, I have been listening that there is a large amount of black money in our country and this black money gets deposited in foreign banks. It would be better if our country evinces interest in this matter and makes efforts to get that money back. I would like to press the demand for a White Paper to be tabled in the House showing all the progress made in this matter.

For the last five or seven days, rising prices of essential commodities has generated a lot of agitation and concern among the people of our country. This inflation is not only due to the mismanagement of the economy but also due to the scandals relating to export and import. So there should be a Joint Parliamentary Committee to look into this matter. We should not forget that in the year 2008 the Government gave relief to the farmers and, in the same year, 16,196 farmers committed suicides.

The issue of electoral reforms is also very important. A number of Committees have been constituted for this purpose which has given numerous recommendations. One of the recommendations given was that, as far as possible the electoral expenses should be borne by the Government. Now, a new issue in the form of paid news has come up. The Election Commission should take cognizance of this issue. Secondly, we should ensure that the elections to Lok Sabha and State Assemblies are held simultaneously after every five year. For this, we will have to introduce an amendment to the Constitution. It will benefit the governance as well as polity of the country and the expenses too will come down.

Now, I shall broach another important issue. Since Agra talks, it was our consistent stand with regard to Pakistan that terror and talks cannot go on hand-in-hand. It was this stand of India which ensured the failure of Agra talks. In 2004, exactly after three years past the Agra talks, General Musharraf stated that Pakistan will not allow its territory to be used for subversive activities against

India. Now, following 26/11, the Hon. Minister for Home Affairs has himself kept on telling us that the validity of the dossiers, which we give to Pakistan, is questioned by them. They say that this does not constitute any evidence and comes in the realm of literature. But it seems that there is no unanimity within the Government itself in this regard. It creates the impression that the American pressure has led our Government initiating the dialogue process with Pakistan. We can change our history but not geography. Interest of the country should be seen first. We all would like and everybody wants that India befriend with Pakistan, harmony be evolved in between them. It has been stated in the report of National Intelligence of USA that Pakistan is of the view that it will take action against only those terrorist outfits who are against Pakistan and they are not concerned with any others.

The Chief of Army Staff of India is in the knowledge of large number of terrorists ready to infiltrate into country. What will come out of the dialogue if we are in such a situation. We have seen the Kashmir of pre-1953 when our President had no right on Kashmir. Mumbai was made victim of such a dreadful attack on 26.11.2008 in which a number of people were killed, even then we are in constant touch with Pakistan. Nothing would be achieved from remaining in such constant touch. I admit that this is a very serious issue for me and I feel that the direction towards which this Government is going on and in this situation if any secret agreement is done we will have to face serious consequences. We cannot repatriate the Pundits displaced from Kashmir.

All these things create serious concern. I would submit that in his reply Hon. Prime Minister should disclose the facts discussed officially or unofficially in the dialogue held till date with regard to Kashmir. New President of America also repeatedly reiterated during his election campaign that he will put his full strength in the resolution of Kashmir problem if he is elected whereas as per the policy of America, it would not intervene until requested by both the countries India and Pakistan. Therefore, I expect the Government to tell us fully and frankly whatever has been discussed about Kashmir should be told in the House. I request with all

seriousness that India's sovereignty should not be diluted.■

राष्ट्रपति का अभिभाषण दिशाहीन

& MKW ej yh eukgj tk' kh

अध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो कुछ चर्चा हुई, उसे मैंने बहुत ध्यान से सुना। उनके भाषण को भी बहुत ध्यान से पढ़ा। उसमें उन्होंने बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये हैं, जिनकी विस्तारपूर्वक चर्चा बहुत से विषयों पर हो चुकी है और शायद बहुतों पर बजट के समय की जा सकेगी। लेकिन कुछ खास बातें जो उन्होंने अपने कई अभिभाषणों में कही हैं, उसमें से एक जो उन्होंने जून, 2009 के भाषण में भी कही थीं, वह यह है कि मेरी सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नामक एक नया कानून बनाने का प्रस्ताव करती है, जो एक ऐसे ढांचे के लिए सांविधिक आधार मुहैया करायेगा, जिसमें सभी के लिए खाद्य सुरक्षा का आश्वासन हो। अभी दोबारा भी उन्होंने इस बात को फिर से दोहराया है और कहा है कि —

In the longer term our food security can be ensured only through sustained efforts. My Government is committed to bring in legislation to ensure food security. ?

It has also been said:

"My Government continues to accord highest importance to ensuring relief to the aam aadmi on food prices."

हमारे वित्त मंत्री महोदय ने भी अपने भाषण में कौटिल्य का उदाहरण देते हुए कहा कि "इस प्रकार, एक बुद्धिमान महा समाहर्ता राजस्व संग्रहण का कार्य इस प्रकार करेगा कि उत्पादन और उपभोग अनिट रूप से प्रभावित न हों। लोक सम्पन्नता, प्रचुर कृषि उत्पादकता और अन्य बातों के साथ वाणिज्यिक समृद्धि पर वित्तीय सम्पन्नता निर्भर करती है।" इसका अर्थ यह है कि पिछले और उससे पहले के बजट में भी इसी प्रकार की बातें कही गयी हैं। खाद्य सुरक्षा महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषणों का सारांश है, जिसे मैंने आपके सामने रखा। खाद्यान्नों के मूल्यों पर भी नियंत्रण रखने की बात

कही जा रही है और ये घोषणाएं की जा रही हैं कि ये बहुत जल्दी नियंत्रित हो जायेंगी। लेकिन आज भी समाचार-पत्रों में है कि 18 प्रतिशत की दर से खाद्यान्नों के मूल्य बढ़े हैं और ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी जो कह रहे हैं, जो आपको संकेत दे रहे हैं, सरकार की नीतियों के बारे में बराबर कह रहे हैं, उनका अनुपालन, मैं समझता हूँ कि यह सरकार करने में असमर्थ रही है। अब जरा देखें कि खाद्य सुरक्षा की जो बात कही जा रही है, इसके निहितार्थ क्या हैं? बहुत पहले पंडित जवाहर लाल नेहरू ने एक वाक्य कहा था कि "Everything can wait but not agriculture-" सब चीजें रुक सकती हैं, लेकिन कृषि नहीं रुक सकती। मुझे देखकर अफसोस हुआ कि आजकल हमारी सरकार की तरफ से अमेरिका के साथ हमारी खाद्य सुरक्षा को सुरक्षित रखने के लिए जो बातें हो रही हैं, तो वहां का क्या रुख है? Mr. Earl Butz, the former Agriculture Secretary of USA had made a statement. In that he said: "Food is a weapon. It is now one of the principal tools in our negotiating kit-" वह अनाज को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं और कर रहे हैं। जिन देशों में अनाज कम होता है, उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं और उनकी आर्थिक और राजनीतिक नीतियों को प्रभावित करते हैं। इसलिए खाद्य सुरक्षा बहुत आवश्यक चीजें हैं यानी खाद्य के मामले में हमें पूरे तौर पर आत्मनिर्भर होने की जरूरत है।

लेकिन हो क्या रहा है? मैंने इस मामले में कुछ बजट प्रावधानों को देखा, मैं ज्यादा की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर आपका ध्यान दिलाऊंगा। यह कहा जाता है कि कृषि के लिए हमें बहुत कुछ करना है और किसानों के लिए हमने इतना दे दिया है, किसानों के लिए हम यह कर रहे हैं, लेकिन जरा उसकी गहराई में जाइए, जो किसानों को ऋण और सहायता देने की नीति है, जरा उसके पंच को समझिए। There is a four-pronged strategy for agriculture. The first of these are: agricultural production. It could mean anything for anybody. The other three are: gold mine for large corporations, but not for the farmers. जो कुछ और किया जा रहा है, बड़े पूंजीपति, बड़े उद्योगपति के लिए है, छोटे किसानों के लिए नहीं है। आप देखें कि एक नीति बनाई गयी है, रिडक्शन इन वेस्टेज ऑफ प्रोड्यूस और यह कहा गया है कि इसमें हम उन सारी चीजों के लिए ऋण देंगे, जो इस वेस्टेज को रोकेंगे यानि कोल्ड स्टोरेज

बनाएंगे या दूसरे इस तरह के कार्य करेंगे। इसमें कहा गया है कि 25 करोड़ रूपए तक एग्रीकल्चरल क्रेडिट के रूप में दिए जाएंगे। 25 करोड़ रूपए ऋण लेने वाले कितने किसान हैं, यह मैं कृषि मंत्री जी से पूछूंगा और वित्त मंत्री जी से भी कहूंगा कि जरा इसका हिसाब दें कि 25 करोड़ रूपए के ऋण कितने किसानों ने लिए हैं जो वास्तविक खेती करते हैं? छोटे किसान को 25,000 रूपए लेना मुश्किल है, लेकिन 25 करोड़ रूपए किसको मिल रहे हैं? एग्रीकल्चरल लोन के नाम पर किसी भी उद्योगपति को मिल सकते हैं जो यह कहेगा कि मैं कोल्ड स्टोरेज बना रहा हूँ, जो कहेगा कि मैं एक रेफ्रिजरेटेड यातायात बना रहा हूँ। उस कंपनी को ये 25 करोड़ रूपए मिल जाएंगे और यह एग्रीकल्चरल लोन उन टर्म्स पर मिलेंगे, जो किसान के नाम पर मिल रहे हैं। वहां ऋण लेना पड़ता है और यहां अगर 25 करोड़ रूपए लीजिए तो शायद इसके लिए कमीशन भी दिया जाएगा कि आप 25 करोड़ रूपए ले लीजिए। यह कैसी खाद्य सुरक्षा की बात है? यह किस किसान के लिए आप बात कर रहे हैं? आप आगे देखिए, इसमें कहा गया कि किसान बाहर से भी खेती के लिए ऋण ला सकते हैं। कौन लाएगा? केवल बड़े कारपोरेशन्स लाएंगे, छोटा किसान तो नहीं ला सकता है। यह कौन से एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए, खाद्य सुरक्षा को ठीक रखने के लिए आपने नीतियां बनाई हैं? किसानों को जो कर्ज दिए गए हैं, एग्रीकल्चरल क्रेडिट के रूप में, जो 10 करोड़ रूपए से ज्यादा हैं, 25 करोड़ रूपए तक हैं या 25 करोड़ रूपए से ज्यादा हैं, वे किसके पास हैं। उनकी एक सूची इस सदन के सामने आ जाए तो पता लग सकेगा। इसमें एक और तमाशा हुआ है कि सालों में 25,000 रूपए ऋण लेने वाले किसानों की तादाद घटी है और 10 करोड़ रूपए से 25 करोड़ रूपए तक कर्ज लेने वाले एग्रीकल्चरल लोनर्स की तादाद बढ़ी है। मैं नहीं समझ पाता हूँ कि किस तरह इससे कृषि उत्पादकता बढ़ेगी और इससे किस प्रकार से आप खेती को आगे ले जा सकेंगे। आप बार-बार यह कहते हैं कि हमने 70,000 करोड़ रूपए किसानों को दे दिया। यह पैसा आपने एक बार दिया, लेकिन आप बड़े कारपोरेशन्स को कितना माफ करते हैं? अगर आप देखें, कभी 80,000 करोड़ रूपए, कभी 70,000 करोड़ रूपए, कभी 60,000 करोड़ रूपए हर साल दिए जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी या वित्त मंत्री जी सदन को यह अवगत कराएं कि पिछले पांच सालों में हर वर्ष कितने ऐसे बड़े कारपोरेशन्स को लोनर्स माफ किए गए हैं या रिलीफ दिया गया है, चाहे वह टैक्स के द्वारा हो, एक्साइज के द्वारा

या अन्य किसी माध्यम से दिया गया हो। अगर आप वह 60,000 या 70,000 करोड़ रूपए हर साल उनको दे रहे हैं और एक बार आपने किसान को 70,000 करोड़ रूपए दे दिए, वह भी किसान को नहीं, किसान के नाम पर बैंकों को दे दिया, तो मैं नहीं समझता कि उससे आप किसान का कोई भला कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि आप कैसे इस काम को कर रहे हैं? अभी भी हालत यह है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं और अभी दो-चार दिन पहले उड़ीसा में 50 हंगर किल्स किसानों ने किए हैं, लेकिन पिछले सालों के जो आंकड़े हैं, करीब-करीब 1.5 लाख किसानों ने पिछले सालों में आत्महत्या की है। हर साल किसानों द्वारा आत्महत्या हो रही है, अभी भी इसमें कमी नहीं आई है। 15,000-16000 किसान हर साल आत्महत्या कर रहे हैं। यह क्या स्थिति है? किसी-किसी राज्य में तीन हजार-चार हजार किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सबसे अधिक अफसोस की बात यह है कि माननीय कृषि मंत्री जी के राज्य में भी ऐसा हो रहा है। वहां भी कमी नहीं आई है, जैसे देश में कमी आई है, उसी हिसाब से कमी आई है, लेकिन आत्महत्याएं रुकी नहीं हैं। इसलिए किसानों की आत्महत्याएं नहीं रुक रही हैं, नहीं रुक रहीं, हंगर डैथ्स नहीं रुक रही हैं, लोगों का मैलन्यूट्रीशियन नहीं रुक रहा। आपको मालूम होना चाहिए कि विश्व के पटल पर कुपोषण दूर करने में अभी बहुत पीछे हैं, हमने उसे पूरा नहीं किया है। तो आप क्या करना चाहते हैं, किस तरह से आप देश की इस खाद्य सुरक्षा को संरक्षित करना चाहते हैं? हमें बताया गया कि कानून बनाना चाहते हैं। मैं आज कृषि पर बात नहीं कर रहा, वरना मैं आपको बता सकता था कि उत्पादकता के मामले में भी आप क्या कर रहे हैं। आप उत्पादकता नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि जिन देशों के साथ आप समझौता कर रहे हैं, मैं उस पर बाद में आऊंगा। वह उत्पादकता बढ़ाने का सवाल नहीं है, वह एग्रीकल्चर को को एग्री बिजनेस में बदलते हैं, उनकी रूचि आपके देश में कृषि उत्पादकता बढ़ाने में नहीं है। आपकी मार्केट्स को लेने में उनकी रूचि है। आपके बीज के व्यापार को लेने में उनकी रूचि है। आपके यहां अपने पेस्टीसाइड्स फंक्ने में उनकी रूचि है। आपके यहां उत्पादकता बढ़ाने में उनकी रूचि नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके पास सरप्लस फूड है। आपके यहां अगर अनाज कम होगा, आप उनके वहां से इम्पोर्ट कर लेंगे। इसलिए उस नीति पर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए कि इस तरह से कैसे आप देश की खाद्य सुरक्षा करेंगे। कहते हैं कि हम कानून बनाकर करेंगे। मुझे

कभी-कभी हंसी आती है कि सरकार के लोग शायद यह समझते हैं कि मॉल्स में, सुपर मार्केट्स में अगर अच्छे पैकेट्स में रखा हुआ विदेशी अनाज है तो खाद्य सुरक्षा हो गई और उत्पादकता बढ़ गई। अनाज की उत्पादकता मॉल्स में नहीं बढ़ती है, दुकानों में नहीं बढ़ती है, अनाज की उत्पादकता खेतों में बढ़ती है, खलिहानों में बढ़ती है और उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है, किसानों की तरफ आपका ध्यान नहीं है। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से मुझे हैरत होती है कि वह बार-बार कह रही हैं, लेकिन आपके कान पर जूं नहीं रेंगती है। आप उस तरफ कुछ ध्यान नहीं देते हैं। जब तक आपकी नीति किसान फोकस नहीं होगी, तब तक न तो आपके देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, न आपको आंतरिक और बाह्य सुरक्षा में मदद मिलेगी, आप इस देश का विकास नहीं कर सकेंगे। भूखे पेट का हिन्दुस्तान किसी रास्ते पर नहीं चलेगा। इसलिए पहली जरूरत है हिन्दुस्तान को हंगर फ्री बनाएं, भूख मुक्त हिन्दुस्तान बनाएं, जीरो हंगर की पॉलिसी बनाएं। मैं आपको बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जब तक आप जीरो हंगर पॉलिसी नहीं बनाएंगे, तब तक हिन्दुस्तान आग नहीं बढ़ेगा। आप कहते हैं कि हम कानून बना रहे हैं फूड सिक््योरिटी के लिए। मुझे बड़ी खुशी होती, अगर इस कानून से आप जीरो हंगर ले आते। लेकिन पहले यह देखें कि इस देश में भूखे कितने हैं। इसी पर आपके यहां एकमत नहीं है। आप बिलो पावर्टी लाइन की सीमा को निश्चित नहीं कर पाए हैं। कोई सरकार नहीं कर पाई, हमने भी कुछ किया था, आप भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन वह ग्राउंड रिएलिटी से बहुत दूर है, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। आपने एक कमेटी बनाई, उसकी रिपोर्ट मेरे पास है। "Expert Group to advise the Ministry of Rural Development in the Methodology for conducting the Below Poverty Line Census for the Eleventh Five Year Plan" इस रिपोर्ट को आप गहराई से पढ़ें और देखें। मैं नहीं समझता आप इसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि यह एक बिल्कुल जमीनी स्थिति को हमारे सामने रखती है। इसलिए इसे गहराई से समझें और इसमें राजनीति न करें। हमने 28 प्रतिशत किया और आपने 27 प्रतिशत किया, यह बराबर मेहरबानी मत करिए। यह देखें कि जमीन पर कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। कौन गरीब है, कौन दरिद्र है। खाली गरीब ही नहीं, दरिद्र कौन है। कौन ऐसा है जो दो जून खाना तो क्या, एक जून भी खाना प्राप्त नहीं कर सकता है। वह गरीबी की सीमा के नीचे बहुत दूर तक नीचे है। इन सारी चीजों को आप देखें तो यह कमेटी

कहती है "Food security is need for all - and not only for those who are officially Below the Poverty Line भोजन की सुरक्षा सबको मिलनी चाहिए, फिर वे यह कहते हैं "This issue is particularly relevant for combating food-related hunger because as we will argue later in this Section, the number of food deficit people has at least doubled the number of officially declared people in India, thus there is every case for enlarging the category of those entitled to cheaper food from the Government. "उन्होंने यह संख्या 50 प्रतिशत तय की है कि कम से कम 50 प्रतिशत होनी चाहिए। इसी कमेटी के कुछ सदस्यों ने कहा है कि यह 50 प्रतिशत क्यों, अगर सही आंकड़े लाए जाते हैं तो सारी स्थिति को देखकर शायद यह संख्या 70-75 प्रतिशत तक जाएगी, 50 प्रतिशत पर ही क्यों। मैंने जब इसे देखा है, इसमें एक भावना उनके दिमाग में भी काम कर रही थी कि सरकार के लिए ज्यादा कठिनाइयां पैदा न हों। यह केवल सरकार का सवाल नहीं है, सारे देश का सवाल है। आपके लिए हो या हमारे लिए हो, अगर इस देश के अंदर 80 प्रतिशत गरीब हैं तो इस सदन का कोई सदस्य ऐसा नहीं होगा कि जो 80 प्रतिशत के लिए इंतजाम करने के वास्ते सरकार के सामने आगे न आए। वह चाहे बिहार में हमारी एनडीए सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश या गुजरात में बीजेपी की सरकार हो या पंजाब में हमारी सरकार हो। अगर 80 परसेंट लोगों के लिए इंतजाम करना है तो करना है। इस देश के किसी भी आदमी को भूखा नहीं रहने देना है और इसके लिए हम साथ देने को तैयार हैं। लेकिन अगर आप इसका रास्ता अमरीका के साथ समझौता करके निकालना चाहते हैं, अगर आप इसके लिए बीटी कॉटन, बीटी ब्रिजल और जिनेटिकली मोडिफाइड फूड देकर करना चाहते हैं तो उस पर बहस होगी और देश में तीव्र मतभेद होगा। आप देश की कृषि- व्यवस्था को देखिये। कालाहांडी के बारे में कहा जाता है कि वह भूखग्रस्त क्षेत्र है, लेकिन आंकड़े यह बताते हैं कि कालाहांडी से हजारों टन धान संग्रहीत भी होता है और वहां सबसे ज्यादा भूख भी होती है। मेरा कहना यह है कि आप इस रिपोर्ट को गहराई से देखें। एक दूसरी रिपोर्ट हमारे माननीय तेंदूलकर साहब की है। उन्होंने आपको कुछ मापदंड दिये हैं। आप उन्हें जरा जमीन के साथ जोड़िये, कीमतों के साथ जोड़िये, लोगों की बदहाली के साथ जोड़िये और आप मेहरबानी करके सबसे पहले गरीबी की परिभाषा ठीक

कीजिए। आज हालत यह है कि दुनिया के बहुत से देशों में अनाज की समस्या है, खाने की समस्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके लिए लोगों ने क्या किया? ब्राजील में, वर्ष 2003 में, वहां के प्रेसीडेंट ने कहा कि हम हरेक आदमी को दिन में तीन बार खाना खिलाएंगे और चार करोड़ साठ लाख आदमियों को उन्होंने खाना खिलाया और उसके लिए 12 मिलियन डालर वर्ष 2005 में खर्च किये। फिर इजीप्ट ने अपने यहां यह काम किया और दो मिलियन यूएस डालर अपने यहां खाना खिलाने पर खर्च किये। फिर मैक्सिको ने यह काम किया। उनका ह्यूमन डिवेलपमेंट प्रोग्राम वर्ष 1997 में शुरू हुआ और 40 लाख घरों को एक मिलियन यूएस डालर खर्च करके खाना खिला रहे हैं। इसी तरह से अमरीका में भी 31.6 मिलियन आदमी यानी दस में से एक आदमी फूड स्टेम्प प्रोग्राम से लाभान्वित होता है। अगर अमरीका की यह हालत है जो दुनिया में सबसे ज्यादा फूड सरप्लस देश है तो हमारी क्या हालत होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप किधर जा रहे हैं? आप इस देश को भूखों का, बीमारों का, अशिक्षितों का देश क्यों बनाते जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पिछले साल ही, डेढ़ करोड़ आदमी इस देश के अंदर गरीबी की सीमा रेखा में चला गया है। हर साल अगर गरीबी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी तो किस आधार पर हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी ने यह कहा है कि हम आने वाले समय में, इस देश को विश्व की महानतम समिति में खड़ा करेंगे। आप वर्ष 2015 तक भूख को आधा करने के लिए कमिटेड हैं। लेकिन मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है कि आप वर्ष 2015 तक, इस देश में भूख को आधा कर पाएंगे। मुझे खुशी होगी अगर यह काम किया जाता है और उसके लिए कोई रोड-मैप होगा तो सारा सदन आपकी सहायता करेगा, मगर मुझे कुछ नजर नहीं आता है। कभी इस पर चर्चा होगी तो हम आपको रास्ता बता सकते हैं, दिशा दे सकते हैं, मगर अमरीका से जो आप समझौता कर रहे हैं, जिसे आपकी कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिसे आपने सदन के सामने नहीं रखा है, भगवान के वास्ते उसका पुर्नरीक्षण करें और हिंदुस्तान के किसान को अमरीका का पिछलग्गू न बनाएं। हम 8000 साल से इस देश में खेती कर रहे हैं, वे 300 साल से खेती करना जानते हैं। हमारी जैव-विविधता को आप नष्ट होने से बचाएं। हमारी धान की हजारों जातियां खत्म हो चुकी हैं, हमारे फूल-पत्ते, जड़ी-बूटियां खत्म हो रही हैं। आप भगवान के वास्ते किसान को, आम आदमी को साथ लें, ये अमरीकन वैज्ञानिक हमारे देश के लिए उपयोगी नहीं हैं। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, विज्ञान को थोड़ा-बहुत

समझता हूँ और जितना मैं अमरीकन्स को समझता हूँ, उनकी दुर्नीति को समझता हूँ, इसलिए अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से बहुत स्पष्ट रूप से महामहिम महोदया को चेतावनी दे रहा हूँ कि इस देश की खेती अगर आपने अमरीका का गुलाम किया, तो आप इस देश की आजादी को नहीं बचा सकेंगे।

आप पता नहीं इस देश को कहां ले जाएंगे? यह देश भूखे नंगों का देश बन जाएगा, इसके लिए मुझे स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री जी से कहना पड़ता है कि आज आप मुस्कुरा रहे हैं। मुझे अफसोस होगा कि किसी दिन आप रोएंगे कि आपकी नीतियों ने देश को इस स्थिति में पहुंचा दिया है। इस देश को इसके लिए रोना होगा। मैं आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि इस देश की खेती को, इसकी परम्परा को स्वाधीन रहने दीजिए। इस देश के किसानों को काम करने दीजिए, इसे अमरीका के हाथ में गिरवी मत रखिए।

महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात देश की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा के बारे में कही है। खाने के बाद अगर कोई चीज जरूरी है, तो वह सुरक्षा है। बहुत समय से संसद में डिफेंस के बारे में चर्चा नहीं हो पाई है। आप कभी चर्चा कराइए कि देश में सुरक्षा के क्या हालात हैं। आज भी हमने अखबार में पढ़ा है कि कश्मीर में घुसपैठ हुई है। हमारे गृहमंत्री जी कहते हैं कि सिक्कोरिटी में ढील हुई है, गिरावट आई है। यह क्या बात है? देश का व्यक्ति अपने आपको असुरक्षित महसूस क्यों कर रहा है? बाहर से जो आक्रमण होने की संभावना रहती है, उसके लिए हम क्या करें? हम जैसे खेती को अमरीका के साथ जोड़ रहे हैं, वैसे ही हम समझते हैं कि समय आने पर वह शायद अपना न्यूक्लियर ट्रिगर हमारे लिए छोड़ देगा और हमें बचा लेगा। आपकी प्रतिरक्षा की जो सामग्री बन रही है, वह बहुत विचित्र है। वह केवल पाकिस्तान ओरिएंटेड है, लेकिन खतरे दूसरी तरफ से भी हैं। इस बारे में ध्यान देने की जरूरत है। भारत सिकुड़ रहा है।

तिब्बत हमारा बार्डर था, उसे आज आपने हिमालय के फुटहिल्स में ला दिया है। नेपाल जो कभी हमारा एक प्रमुख समर्थक होता था, उसे आपने असहाय बना दिया है। एक तरफ से चीन पाकिस्तान के माध्यम से गोडार तक पहुंचा हुआ है। बंगाल की खाड़ी तक पहुंचा हुआ है, सारे दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के देश आज चीन की गोद में जा रहे हैं। चीन आज सारे क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बनाता जा रहा है। आपकी सामरिक शक्ति और

आर्थिक शक्ति अभी चीन से बहुत पीछे है। जो स्थितियां हैं, उन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए। हम किस आधार पर विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं? हम तो आज के समय में क्षेत्रीय शक्ति भी नहीं हैं। मुझे इस बात का अफसोस है कि जहां हम थे, उससे बहुत पीछे हम चले गए हैं। 1947, 48, 49 में हमारी जो स्थितियां थीं, वे आज बहुत पीछे छूट गई हैं।

चीन ने हिंदुस्तान को बीस-तीस टुकड़ों में बांटने की कोशिशें की हैं। सारे हथियार उसने इस तरह से समायोजित किए हैं। अरुणाचल के ऊपर वह अपना कब्जा बनाना चाहता है। सिक्किम में वह मांग कर रहा है। अक्साइ चीन वह कब्जे में लिए बैठा है। अब जब अक्साइ चीन की बात आती है, तो कश्मीर भी मुझे याद आता है। श्रीमान आडवाणी जी ने इस सवाल को उठाया था। मैं चाहता हूं कि वह सवाल सही परिप्रेक्ष्य में सदन के सामने बना रहे। सदन का प्रस्ताव था कि कश्मीर हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा। मैं चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस मामले में सदन को आश्वस्त करें। यह प्रस्ताव इसी सदन में पास हुआ था। हम हैं, हम तो कह ही रहे हैं। हम तो इसकी मांग कर रहे हैं कि इसे दोबारा दोहराएं। प्रधानमंत्री दोबारा प्रस्ताव रखें और हम उसका समर्थन करेंगे। हाँ, हमारे शरद पवार उसे दोहराएं। हम उसे दोहराना चाहते हैं। देश को आश्वस्त करना चाहते हैं। मैं यही बात माननीय प्रधानमंत्री जी से सुनना चाहता हूं कि कश्मीर भारत का अंग था, है और रहेगा।

मैं दो बातें कहूंगा। एक बात तो यह है कि मैंने प्रस्तावक महोदय का भाषण सुना। इसमें लगभग कोई ऐसी चीज नहीं थी जिस पर कोई टिप्पणी की जाए। लेकिन एक वाक्य ऐसा था जो उन्होंने लालू प्रसाद जी को संबोधित करते हुए कहा कि हम आपसे हिंदी में तब बात करेंगे जब आप और हम वृंदावन में गाय चराने जाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसमें बहुत गहरी बात कही गई है। इसके दो पक्ष हैं – वे वृंदावन में गाय चराने तो तब जाएंगे जब गाय इस देश में बचेगी। जिस रपतार से गायों का वध हो रहा है, मुझे शक है कि उन्हें गाय के बजाय किसी और जानवर को चराने के लिए वहां जाना पड़ेगा। जिस भाषा की बात की है, शायद उस पक्षी का जिक्र किया था, वे केवल उसी की भाषा में उससे बात करते रहेंगे, इस सदन को जो भाषा लगती है। हिंदी सदन की भाषा है। भारत की राजभाषा है, संविधान की भाषा है इसके लिए गाय चराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए पहले अपने दिमाग को चलाइए, ठीक रखिए। आपको हिंदी में बात करनी चाहिए, करनी होगी।

आप न करें तो अलग बात है लेकिन आप उसे चरवाहों के साथ जोड़ रहे हैं।

भारतीय भाषाओं में करें। मुझे इस बात का फख है कि आपने कहा कि आप चरवाहों से हिंदी में बात करेंगे।

देश का चरवाहा भी हिंदी बोलता है, अंग्रेजी नहीं बोलता है। आप इस बात का ध्यान रखें कि हम इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप हिंदी के प्रति इस प्रकार के अपमानयुक्त शब्दों का प्रयोग करें।

मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं। प्रस्तावक महोदय के बाद समर्थक महोदय ने भाषण किया, मुझे भाषण के बारे में उन्हें बधाई देनी है। उन्होंने एक बहुत गहरा सवाल पहचान का उठाया। उन्होंने पहचान यूनीक आइडेंटी कार्ड से जोड़ी लेकिन वह जरा कुछ हल्की हो गई क्योंकि आप इस देश की पहचान एक नंबर से देना चाहते हैं, यूनीक आइडेंटी नंबर। आप इस देश के आदमियों को नंबर बनाना चाहते हैं। यह बुद्ध का देश है, महावीर का देश है, गांधी का देश है, सूफ़ी-संतों का देश है, राम और कृष्ण का देश है, इसकी पहचान नंबर से नहीं होती। आपकी मेहरबानी होगी, आप इस देश को नंबर में मत बदलिए। उसे इंसान रहने दीजिए, उसकी इंसानियत की पहचान रखिए, उसकी परंपरा की पहचान रखिए, उसकी संस्कृति की पहचान रखिए। आप ध्यान दीजिए और भारत की भारतीयता की पहचान दीजिए लेकिन आप क्या पहचान दे रहे हैं कि आप गरीब हैं। आप गरीबों को इस देश के गरीबों की पहचान दे रहे हैं। गुरबत की पहचान देना चाहते हैं। आप क्या देना चाहते हैं? हम भारत को गौरवशाली पहचान देना चाहते हैं। भारत की पहचान दुनिया में महान संस्कृति और परंपरा के तौर पर रहेगी। वे नंबर नहीं हैं। अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए। नंबर में बदलने की नीतियों को देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। मेहरबानी से देश को सही पहचान देने का काम करें। भगवान आपको ऐसी शक्ति दे, बुद्धि दे कि आप इस देश को समझें, इसकी सही पहचान को समझें, परंपराओं को समझें, संस्कृति को समझें, इतिहास को समझें। आप तब जाकर इस देश की नीतियां ठीक बना सकेंगे। (इति)

Synopsis

I have listened the President's Address very attentively. In her Address, delivered in 2009 and, in this year also, she affirmed

that her Government proposes to enact a new law named the National Food Security Bill. She also suggested to rein in the prices of food grains. But, I have a feeling that this Government has failed to implement and follow the directions given by the President. I have gone through the Budget provisions made in this regard. It has been mentioned that the Government would provide loans to those who construct cold storages or put together this type of other things. It has been said that the Government would provide agricultural credit up to Rs. 25 crore. I would like to ask the Government the number of those farmers who actually do farming and have taken this much amount as loan. This facility is being availed by industrialists in the name of agricultural loans. It has also been said that the farmers can raise loans for agriculture from abroad. Who will raise this type of loan? Certainly, the small farmers cannot. Only large corporations can indulge in such activities. What type of agricultural development will be brought about by these policies, which, arguably, have been framed to ensure food security.

The Government has claimed times and gain that they have waived off loans of farmers worth Rs. 70,000 crore. This has been done only once. But, how many times these types of concession have been given to the large corporations. The farmers are still committing suicides. What is the way by which the Government intend to ensure food security? The Government wants to enact a law for food security. But, first of all you have to ascertain the exact number of poor people in the country.

Your Government lack unanimity on this count. The Government has failed to define the Below Poverty Line. Whatever work it has done, does not correspond with the ground reality. The Government had constituted a Committee which said that the BPL people constitute 50 per cent of our population. Some members of this Committee were of the view that this number, perhaps, will touch the 70-75 per cent mark. I have gone into this Report deeply. Perhaps, there was a feeling lurking in their minds that their findings should not trouble the Government. But, this

matter concerns with the future of our country. If we have to make arrangement for 80 per cent of people, then there is no alternative to that and we must have to do it. Even the food surplus countries like Brazil, Egypt, Mexico, America make arrangement to feed their poor and hungry people. The Government is committed to reduce the number of hungry people by half by the year 2015. I would be rather happy if the Government prepare a road map to this effect. The whole House is with the Government on this aspect. But I do not see much in the Government policies.

The Government would be doing a favour to the people of the country if it reviews the very agreement which the Cabinet has approved and likely to be concluded with the USA. The American scientists are of no use to us.

Second important issue is the internal and external security of the country. Our people are feeling insecure. Our defence preparedness is Pakistan centric whereas there are threats from other sides also. China is encircling India from all sides – North, West, East and South. Aksai Chin is under its control. Arunachal and Sikkim are its next targets. In this context, the House would like to have an assurance from the Hon. Prime Minister that Kashmir would remain an integral part of our country.

While concluding I would like to say that Hindi is the official language of the Union and also of the House. Kindly do not deprecate it by associating it with the cowherds. ■

Government has really run out of ideas

- M. Venkaiah Naidu

Hon. Deputy Chairman, Sir, the country is deeply disappointed with the hon. President's Address, because it did not contain any answers to the challenges being faced by the country. Same promises are repeated once again in the Address. If you go through the President's Addresses that were made during the last five years -- after UPA-I and now UPA-II came to power -- you will find almost same assurances, same promises, many of them are repetitive, some of them are forgotten and some of them are not implemented. It has not inspired anybody, even their own allies. They are also disappointed. The Government has really run out of ideas. There is a problem of price rise. There is a problem of economic crisis. There is a problem of unemployment. There is a problem of rural unrest and farmers suicides. There is a problem of Maoist menace across the country. There is a problem of terrorism and terrorist modules are coming into various parts of the country. There is also a problem with our neighbour which is actively engaged to subvert India from time to time and we have the happenings in Jammu and Kashmir. And, just now my friend said some of the burning issues like Telangana. But, this President's Address do not come clear of any of the issue, because, as has been said by our leader, the Government really ran out of ideas. Either the hon. Finance Minister, the hon. Agriculture Minister or the former Finance Minister, during their interventions or during their discourses outside the House, has been able to explain about the price rise. They are only expressing hope that something will happen. भगवान दया करेगा, प्रकृति दया करेगी, कुछ न कुछ होगा We have been hearing this right from the hon. Prime Minister's mouth. All these Ministers have been expressing this hope. I also hope that their hope becomes reality. The country will be happy if the

prices come down. But, Sir, the wishes cannot be horses. We know what is happening. You need to take some concrete steps and action and this Government has miserably failed in doing so. Sir, price rise is an assault on the common man. कांग्रेस ने कहा, 'कांग्रेस के हाथ आम आदमी के साथ'। आज छः साल हो रहे हैं, लेकिन देश की जनता में भावना यह है कि 'कांग्रेस के हाथ माने आम आदमी के साथ विश्वासघात'। मैं आज आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ, माननीय प्रधान मंत्री जी भी यहां पर बैठे हैं, आपके पास महंगाई को रोकने के लिए क्या उपाय है? आपकी रणनीति क्या है? आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? आपने इसके बारे में क्या सोचा है? बहुत दिन के बाद मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाई गई, बाद में एक कमेटी बैठाई गई, लेकिन क्या केवल कमेटी बैठा देने से काम होने वाला है? क्या वही एक मात्र उपाय है? इसके लिए आपने पहले से क्यों नहीं सोचा? इन सवालों के बारे में सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। This price rise is a silent killer. It is affecting the common people and if you go by Suresh Tendulkar's recent Report on poverty estimates, the poverty levels are going up and per-capita expenditure of the ordinary people has gone down considerably. Today, while replying to a question, shocking revelations made by the hon. Minister about the expenditure. He said that per-capita expenditure in rural areas is Rs. 446 per month and when it comes to urban areas it stands at Rs. 578 per month. On the one hand, the Government is saying that there is recession and, on the other, the President's Address is saying that we have enhanced the purchasing capacity of the people through NREGA and other schemes. On the one hand, you are saying that purchasing power of people has gone up and, on the other, statistical data provided by the NSSO and also Tendulkar Committee contradicts the same. I hope the hon. Prime Minister who is a learned person in economy and economics will focus his attention on this dichotomic situation. Why is it happening like this? If there is recession, there should be lack of money. But, on the other hand, you are saying that purchasing capacity has gone up. There is a contradiction. The UPA Government has inherited a robust economy. It is not that they inherited bad economic situation which they are not able to manage. Sir, I quote from the Economic Survey of July, 2004. It says, "The economy appears to be in a resilient mode in terms of growth, inflation and balance of payment, a combination that offers large scope of consolidation of the growth momentum which continued macro economic stability." These are not the words of the BJP or our NDA. This is the survey presented by the then hon. Finance Minister, Mr. P. Chidambaram, to Parliament. You

inherited such a comfortable level of foodgrains and also the highest foreign exchange and the lowest inflation. At that time, during the NDA regime, there used to be no queues, no waiting list, no shortage, no black-marketing for any of the goods. But what is the situation, today? I need not go on explaining it. I would like to humbly submit to this House that one of the main reasons for the price rise is the corruption involved in this, the scams in the export and import of foodgrains -- wheat-rice, wheat-wheat, wheat-sugar. The successive actions taken by this Government, from time to time, in the last few years were such that you exported at cheaper prices and imported at higher prices. What is this happening? Why is the Indian Government doing this? You provide Indian farmers Rs. 850-1,000 per quintal and you import at Rs. 1600 per quintal. I can understand that wheat or rice cannot be produced overnight. You need a plan for that. But 5-6 years' time is not an ordinary time. You could have changed your strategy. You could have laid more stress on those crops or those grains which were in shortage. But you did not do that. You did not pay attention to that. You are saying there is lack of production; you are saying there are global problems; you are saying this thing or that thing. These things are there in each and every speech of yours. During our regime also there were cyclones, there was drought, there was a massive earthquake in Gujarat. We tackled all this. We released around 40-60 lakhs tonnes of foodgrains to different States; and, there was no problem. There was enough food for work. Why have you not done it? On the one hand, the Minister says that, now, there is enough production; on the other hand, you have not released foodgrains in the market. Why are you allowing the prices to go up? What is your response? That's why the BJP wants, the people want that a Joint Parliamentary Committee should be set up to inquire into the scam of export and import of foodgrains, including sugar. The Government should not have any objection to that. If, after the inquiry, you come out with flying colours, the country will be satisfied. Until this matter is not cleared, the doubts will keep on lingering in the minds of the people. There were many articles, many items in the newspapers, many expert people also feel that what has happened is wrong. Is it because of this scam, which is involved, that the Government is shying away from its responsibility? You ordered export of sugar even though sugar shortage was there in the country. You also ordered export of rice to African countries even though rice shortage was there in the

country. That's why we are demanding an inquiry into the matter. But nobody is responding to that. I don't know why it is happening. It is not for the sake of criticism that I am saying this. जब-जब कांग्रेस आती है, महँगाई साथ लाती है। Is it a co-incident? I am not able to understand this. You see, it happened in 1980. It happened in 1991. It again happened, now, when the Congress Party came to power. Why is there sudden increase in the prices? Earlier, the sugar was Rs. 10 per kg. Now, it has gone up to Rs. 35-40 per kg. The rice was Rs. 12-13 per kg. Now, it has gone up to Rs. 32-35 per kg. Daals, in some States, it is nearing Rs. 100 per kg. Oil is also nearing Rs. 100 per litre. What was the price situation in our time? Let us have a debate on this. My friends, who are in power for 5-6 years, still criticise Opposition parties. When we were in power, except on one occasion during Delhi Assembly Elections, the prices were never allowed to rise; they were within the limits. We were able to control the prices. When the prices of onion went up in Delhi, you were the beneficiary. You won in Delhi elections at that time. That is a different matter. But in your regime, even the prices of potato, tomato, every vegetable, and every foodgrain are going up day by day and there is no explanation by the Ministers. As the Leader of the Opposition said, you are blaming each other. The Congress Party says something; the NCP says nobody, in the country, has died without eating sugar. Is this an explanation? One Minister is blaming the other Minister. But it is a collective responsibility. You are all equally responsible for all this. And, I am also surprised that the Congress leadership is also silent on this. Congress used to play a pro-active role and intervene and statements used to be released that on the intervention of so and so Congress leader this has been done; they met the Prime Minister. But this time, on the issue of price rise, I don't know what has happened to the Congress leadership.

Sir, the Congress Leadership is silent. I would like to have an explanation from the Congress Party as to why this is happening because we have a Parliamentary system where parties also matter much. Sir, Consumer Price Index in India, today, is the highest amongst all the countries of Asia Pacific. The murderous price rise in India is the single most important issue today. Everywhere, whether you talk to anybody in train, in bus stand, in colleges, in universities, in restaurants or in any four corners, you will find people talking more and more about price rise. Except Congress Party, everybody is discussing it. Sir, our scheme was Antyodya,

your scheme seems to be Aamirodya- Words for the poor and deeds for the rich seem to be your motto. Otherwise, tell us, what have you done to contain the prices? What have you done, Sir? When the prices are rising and food articles are not within the reach of the common man, our Finance Minister, without bothering about the sensitivity of the situation, just announces in the Budget that petroleum prices will be hiked. The entire country was worried and agitated. The Parliament could not function for two, three days. The entire Opposition was at its feet. And, in Lok Sabha, after this announcement was made, the Opposition walked out. Our Congress friends, without answering the core issue find fault with the Opposition walking out. I think the hon. Prime Minister, if my memory is right, also seems to have commented on that. The former Finance Minister also commented on that. Here, I would like to respectfully submit, Sir, why this double standard? What you do in Parliament, Sir? You can talk out or you can walk out. That is a way provided in the Parliamentary system. It is within our right to do this. Walking out is within our right. You do not want to talk out or walk out; you want to have frequent break-outs. Sir, I would like to say what the same Congress Party did in Gujarat. आप लोगों ने गुजरात में क्या किया? सर, गुजरात में कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने बजट के समय में वाकआउट किया और उसका boycott किया। इसका कारण क्या था? इसका कारण महंगाई नहीं थी।

अरे भाई आपको गुजरात की जनता ने दो बार नॉकआउट किया। अब आप ज्यादा न बोले तो अच्छा है।

Sir, in Lok Sabha and also in Rajya Sabha, there was a serious discussion. Even some of the friends supporting the ruling Party are also concerned about the price rise. Of course, their sincerity will be put to test tomorrow or day-after-tomorrow, whenever an occasion comes in the House. But my point is you walked out in Gujarat, you did not hear the Budget Speech. Do you know what was the reason, Sir? The reason was not the price rise, not the people's problem; you walked out because the Speaker of the Gujarat Assembly had permitted the Finance Minister, because of his health reasons, to make his Budget Speech sitting. बैठ कर बजट स्पीच पढ़ रहे हैं, इसलिए हम वाकआउट करेंगे। अगर वे बैठ कर पढ़ें या खड़े होकर पढ़ें, इससे क्या फर्क पड़ता है? इसका क्या असर पड़ने वाला है?

Figures are not going to change, whether he makes his Speech sitting or standing. It is a human problem; one has to understand. Now, with what face, the same party is criticising us? You are

finding fault with the Opposition walking out in Lok Sabha. It is our legitimate right. You have discussed Gujarat hundred times. Sir, this is the double standard of the Congress Party. I hope my friend, Mr. Chidambaram, is hearing what I am saying because he has been vocal outside, criticising us on this count and the Congress Spokesperson also taking note of the same. Sir, the people and the Opposition were aghast. While the issue was being discussed in both Lok Sabha and Rajya Sabha, the Finance Minister, without any concern about the sensitivity of the people and the common man and the promise they made in the Congress election manifesto, he had the audacity to increase the prices of petroleum products which will have a cascading effect on the prices of essential commodities. If it is simply on petroleum or diesel, one can understand, Sir, but it will have effect on transport charges, vegetables, milk, dal, tel, coal, steel and everything.

आपके लिए महंगाई कोई issue नहीं है, इसलिए आपको कोई चिंता नहीं है, हमारे लिए महंगाई बड़ा पेनम है, देश की जनता के लिए बड़ा issue है। सर, वित्त मंत्री ने यह भी कहा and it really makes us worry. About Parikh Committee recommendations, the Minister has gone on record saying, 'the petroleum product prices will be taken care by the Petroleum Minister.' That means, there is one more dose in the offing, another petro-bomb in the offing! If the Prime Minister or anybody from the Ruling Party can say no to such a proposal, we will be happy; the country will be relieved. He has left the scope for, after the Budget Session is over, the Government intends to increase the price of petroleum products once again through backdoor. That seems to be the reason; otherwise there was no need for the Finance Minister to mention about this. Sir, that is why I am saying that 100 lakh tonnes of rice was exported; around 100 lakh tonnes of wheat was also exported. The price was 9-10 rupees and the import price is 24 rupees and at times, it was 32 rupees. That is why we call it a big scam and we demand that there should be a Joint Parliamentary Committee. The Joint Parliamentary Committee must go into the whole gamut of issues such as reasons for food inflation despite bumper crop as claimed by the Minister last year, sufficient availability, manipulative export and import of sugar, wheat, etc. The JPC should also enquire as to why 49 lakh tonnes of sugar was exported in the year 2008-09 at Rs. 12.50 and now imported at 36-40 rupees. This is an important issue. I request the hon. Prime Minister to understand the sentiment and try to agree for this demand, i.e., setting up of a

Joint Parliamentary Committee.

Sir, the second issue related to President's Address is, in the President's Address, the Government has claimed that it has taken new measures to strengthen the security to meet the challenges posed by terrorism. What are the new measures? Why the Pune happened? Sir, post 26/11, it was expected that our Intelligence networks would be strengthened. The Ram Pradhan Committee appointed by the Maharashtra Government has submitted a report and in the report, they said that 'Pune will be the possible next target.' 'Pune will be the possible next target.' Sir, Pune is next to Mumbai and Maharashtra Government appointed a Committee and the Committee has opined and gave an input like this. The Committee even visited Pune and still this happens in Pune. What do you explain about it? How do you explain it? The internal security in the country still remains fragile. After one year of its investigation, the Government is clueless with regard to David Headley, Munawwar Rana; about their movements, etc. Sir, the Intelligence failure was evident from the fact that Headley kept on visiting India before and after 26/11. So far, nobody has denied this. All the leads are coming from the Intelligence agencies only as to where he has gone, where he stayed, whom he has met, etc. All these leads are coming out and what the Government is doing? What the Intelligence wing of the Government was doing, we are not able to understand. Sir, whatever advisory notes they send to the States are casual. It says, 'there is a possibility; they send these general advisory notes to all States; be alert; Chennai may be in the hit list, Bengaluru may be in the hit list; Kolkata may be in the hit list.' If you make generalised advisories, people will take it casually. So, what improvement they have made after 26/11 in this regard? The policy, according to me, of this Government seems to be 'condolence for the dead, compensation for the survived.'

जो मर गया, उसके लिए सहानुभूति, जो बच गया उसके लिए, उसकी family के लिए कुछ पैसा। पैसा देना चाहिए, सहानुभूति व्यक्त करनी चाहिए, यह जनतांत्रिक सरकार का लक्षण भी होता है। मगर, उसके आगे क्या किया, उसके बारे में कुछ समाधान देना चाहिए। मुंबई में हुआ, अयोध्या में हुआ, काशी में हुआ, मथुरा में हुआ, औरंगाबाद में हुआ, नागपुर में हुआ, हैदराबाद में हुआ, देश की अलग-अलग जगहों में हुआ। इन विषयों के बारे में अब तक आपने क्या एक्शन लिया, क्या हुआ, सरकार इस बारे में क्या कर पाई, सरकार यह स्पष्ट रूप से सदन को अवगत कराए तो अच्छा होगा।

Sir, my allegation against this Government is, the first stint of the UPA-I on the terrorist front, fighting terrorism or dealing with

terrorists, was absolutely disastrous. The Pak-sponsored terrorism 26/11 has made the Government to realise the seriousness to some extent. They started taking some corrective measures. But there is no forward movement on this. Some Congress leaders have converted suspected dens of terrorists as places of political pilgrimage.

Repeated visits of politicians to these areas have emboldened the enemies of the nation. For example, senior leaders of the ruling party are publically endorsing the claims that action by the Delhi Police at Batla House was a fake encounter. It is a great injustice to the country, to the memory of the persons who have laid down their lives fighting terrorists. You visit places and make speeches. You go to Azamgarh; you go to Batla House and then you make statements. It is not the ordinary people. If an ordinary person had made such a statement, we would not have worried about it. It is the important people, the AICC General Secretaries, who made such statements and, then, our friends, the spokespersons, tried to wriggle out from the embarrassing questions from the media, from the public. This has happened. I am not treating it in a casual manner, Sir. As far as terrorism is concerned, as far as the security of the country is concerned, we are one with you. We are ready to extend you whatever help is needed from an opposition party. The entire country is agitated. How long should you have this? If there is tension within the country, there cannot be any attention on the development. I am also aware of that fact because we have also been ruling the country for some time. Now, the Government must muster courage and must evolve a clear-cut policy to tackle terrorism. There should be a no-nonsensical approach. Politics should not be linked with the issue of fighting terrorism. Religion should also not be linked with the issue of fighting terrorism. A terrorist is a terrorist; he has no religion. Whichever religion they may belong to, you cannot categorise terrorists as Hindus, Muslims and Christians. They are terrorists. They are enemies of the nation. They are destroying our social fabric. So, they have to be dealt with in a firm manner.

Sir, there is another issue and that is of Naxal demands. They have a grand plan. From Pashupati to Tirupati, they want to have a 'red corridor'. That is their stated goal. Secondly, I am also very clear, Sir; I have been watching their movement. Initially, we had some fancy towards their attractive slogans and songs. In my early days in the Legislative Assembly, I used to be tempted sometimes

by the radical slogans they used. But of late, we have realised what they are doing, how they are killing people. Hundreds and thousands of people are being killed across the country, and they label them as police informers. They are also attacking the public. They are attacking public and private property, Government property and destroying the property of the nation. The duty of the officials of the Government is to show absolutely no lenience towards Maoist leaders. We also urge upon the so-called civil rights activists not to dress up these murderous ideas in clothes of legitimacy. I know that it is a very serious statement. The NGOs talk about so-called civil liberties. For whose liberties are they fighting? Is it for the helpless people, adivasis, harijans, dalits and ordinary people, or for the people who are killing the innocent civilians? I am unable to understand what is happening -- sitting in Delhi and giving lectures and sermons to people asking them not to touch them as civil liberties are involved! Liberties of civilians are more important. Ordinary human beings are more important to us than organised people like these, who have a different ideology, who have a murderous ideology. We are not one with them as far as ideology is concerned. Power won't come from the barrel of the gun. Even if it comes, it would not survive for long. This has to be understood and they have to be told this. The Government wants to have so-called talks with them; I do not understand why these talks again. Talks with whom? Talks for what? Talks at what cost? What is the agenda? Sir, I have seen such talks in Hyderabad twice. They use the interim period to recoup and reorganise themselves. Sir, there are so many political parties. If the Maoists and CPI-ML are confident of their ideology, they can leave their arms, they can form a political party, they can contest elections, defeat parties and capture power. Who prevents them from doing that if they have strength and confidence in their ideology? Let them do it! If they want to fight CPM in Bengal, let them come out openly and contest elections or do the same in other parts of the country. But they cannot hold a gun, kill people, kidnap the driver of a train, put people to ransom and then call it revolutionist ideology. We are not willing to accept it. The situation is becoming serious day by day. Around 25 per cent of the total districts in the country have Maoist presence today. If this situation continues, we may have to hand over certain districts to the military in the years to come. That is unfortunately the situation now. There was some incident in Lalgurh. I do not wish to quote what has

transpired in the Committees because it is against the parliamentary rules. Sir, the information available is that certain areas of West Bengal, Jharkhand and other regions are not within the reach of the administration.

You are an independent country and after sixty years of Independence today, you are saying so! In Andhra, Orissa, Chhattisgarh and Jharkhand, there is no political discrimination. They are not criticising this Government or that Government. This issue cannot be dealt with by State Governments alone because, as you know, they hit here and run there for shelter. They have a network and they have their own supporters from various places. If one says that 40,000 sq. km of Indian soil is not within the reach of administration -- this was the information given to us and it was open to hon. Home Minister also -- is it not a challenge to all of us? Is it not the collective responsibility of all of us to fight the situation and to meet the situation? Yes, we live in a democracy. We do not want to kill anybody who have no arms in hands. We don't believe in fake encounters. If the other man is going to fire on you and you tell the Police not to do anything but catch hold of him, is it possible? So, my point is that there has to be a political, educative action plan to educate the people about this menace and they have to be segregated and they have to be isolated saying that their ideology is not acceptable to the system of democracy. We have to fight them out. Law must also take its own course. What steps the Government of India has taken to stop this? Legally and constitutionally, we are one with them. Sir, I have already told you about so-called progressive intellectuals. They are the people with zero level of reality. They do not understand the reality of the situation. They go on criticising the State Governments; they go on criticising the Central Government. They do not go to the reality of the problems. So, my point is that if you want to talk to them, there is nothing wrong in talking in democracy but they must abjure violence and they must give up arms. If they give up arms, then talk to anybody. There is no problem in that. They are also citizens of India, but don't talk out of fear and don't talk in air, be real. Know the problems of people. Innocent people including Adivasis and tribals have been butchered, killed and murdered in different States of the country. What the sin they have committed! Kidnapping and killings of people and hijacking of trains is still happening. Hon. Prime Minister I am sad to say that some of the leaders of the ruling party are speaking their language. I don't say

all. One former Andhra Minister said "I am also naxalite". I said, "If you are naxalite, how can you be a Minister?" You can go and join them. Some people express their sympathy and some people say about socio-economic problems. Sir, we are all there -- the Congress party, the BJP, the Communist party, the Samajwadi party -- to tackle the socio-economic problems. We are doing our bit. Most of us are spending time for years to solve the problems. They are trying to prove that we are not doing anything and they are doing everything. It cannot be acceptable. Coming to talks with Pakistan. Why talks in spite of terror? Terror and talk cannot coexist. आप हर चीज यूएसए के दबाव में क्यों करते हैं? यह impression जनता में है। प्रधान मंत्री जी ने कल कुछ कहा, मैं उसके बारे में अभी कोई व्याख्या नहीं करना चाहता हूँ। मगर मैं उनको convey करना चाहता हूँ कि देश में आम जनता की जो भावना है, अरे भाई, अभी क्या है, वक्त क्या है और चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्या परिवर्तन आया? इस बीच में प्रधान मंत्री जी ने खुद कहा, and the Prime Minister himself accused Pakistan of using terrorism as an instrument of State policy. He also declared that we do not know how to talk and whom to talk in Pakistan. During the Chief Ministers' Conference the hon. Prime Minister said the terrorists and anti-Indian forces are waiting at the borders to cross over to India. This is the statement made by hon. Prime Minister. Sir, is there any change in the attitude of Pakistan afterwards which made you to change your views? Secondly, the hon. Home Minister, Mr. Chidambaram, said the terrorist activities have increased in the recent months. It is an official statement. No meaningful steps were taken by neighbours to stop terrorism. Defence Minister, Mr. Antony, said, "We are not fully satisfied. Pakistan Government had not taken concrete steps to dismantle 42 terror camps and the infiltration numbers have shown distinct jump this year." I again come back to an important point. यह बहुत खतरनाक वक्तव्य गृह मंत्री जी ने दिया, 'Home Minister offer an amnesty to PoK youth.' You will have disastrous consequences on the security of the country. मैं प्रधान मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यह देश के हित में मत कीजिए, यह देश के हित में नहीं है। पाकिस्तान occupied कश्मीर में जो आतंकवादी बसे हैं, ऐसे लोगों को बिना enquiry के फिर से वापस आने देना

Former J&K Chief Minister and present Cabinet Minister, Shri Ghulam Nabi Azad, said that the idea of surrender policy would be used as they are converted by Pakistan to push foreign militants into India. This was a statement by one of the hon. Cabinet Ministers who has enough experience about Kashmir, who had

been the Chief Minister of Kashmir. There are chances of adopting a strategy to push militants into India taking the cover of surrender. This is the danger. If somebody is really changed, हृदय परिवर्तन हो गया, अपनी भारत मां के पास कोई वापस आना चाहता है, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मगर इसका तरीका क्या है, पद्धति क्या है? क्या हो रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, कैसे लोगों को प्रोत्साहन दे रहा है -- यह आपके सामने है, हमारे सामने है और कोई छिपी हुई बात नहीं है, इसलिए यह जो नया कदम उठाने के लिए आप तैयार हो रहे हैं, यह बहुत खतरनाक है, इसके बारे में सबसे चर्चा करने के बाद ही आगे बढ़ना पड़ेगा। What for this dialogue? What is the agenda? What is the purpose? These are the questions people are asking. I would like the Government to make a categorical statement to clear these doubts in the minds of the people. There is no cohesion; there is no co-ordination; there is no co-operation in this Government. Sharmel-Sheikh statement is an indication that there is no cohesion, there is no co-ordination, and there is no co-operation. We have just heard from Dr. Najma Heptullaji about the statement made by our Minister of State for External Affairs. He said, "I did not use the word 'mediator', I used the word 'interlocutor'." Sir, Ministers are supposed to be careful, and the Minister of External Affairs is supposed to be much more extra careful; MEA - extra careful. But, this Minister seems to be 'care nil'. This is not the first time; this is not the second time; this is not the third time. He is a welleducated person, trained in America also for some time. My friends are saying, "That is the problem." I have nothing against him. In fact, Sir, I like youngsters coming up in politics and public administration in the Government because we need to bring them and we need to encourage them. But, the Minister is not able to understand the general philosophy of the country, philosophy of the party in which he is functioning, philosophy of the Government in which he is functioning. And, then there is this 'tweeting'. What is this 'tweeting'? I do not understand. Too much tweeting can lead to quitting...(Interruptions). Remember this; too much tweeting will lead to quitting. He must understand this, and then, he must be very careful. यह कोई मज़ाक का विषय नहीं होना चाहिए। Sir, when I criticise Shri Shashi Tharoor on this count, I don't feel happy. I have always been a critic of the Congress Party from my student days onwards because of ideological differences, not on a personal level. But, at the same time, if the Minister goes on making such statements, I do not know why the Prime Minister is silent on him. He should be properly advised, guided and counselling should be

given to him. I don't use the word 'scolding'. Now, I come to the issue of Telangana. Just now, my friend, Shri Prakash Javadekar, spoke about it. I am not able to understand that responding to my reaction on the appointment of Justice Srikrishna Commission, day before yesterday, the hon. Home Minister made a categorical statement, "Who said that this is not statutory? It is statutory. Justice Srikrishna has the status of a Supreme Court Judge." I am not bothered about the status. We have respect for Justice Srikrishna. We have respect about the wisdom of Justice Srikrishna and other Members of the Commission. There is no casting of aspersions with regard to integrity, with regard to knowledge of those people. The question is: why this Commission? If this is the purpose and this is the interest of the Government and the hon. Prime Minister, why did the Home Minister call the meeting of all political parties? Eight political parties were called to Sachivalaya in Hyderabad by the Chief Minister. They gave some opinions. Some of them changed their opinion later to the amusement of their own supporters and to the astonishment of the people of the State. But, subsequently, taking that as a reason, the hon. Home Minister called a meeting here in North Block. Eight political parties were called. According to him, he had a four-hour lengthy, detailed, meaningful, constructive meeting. Parties have given their opinion. Everything is recorded. Now, you are sending Srikrishna Commission. Srikrishna Commission will go and do what? Again, it will do re-recording. प्री-रिकॉर्डिंग हो चुकी है, बाद में रिकॉर्डिंग हो चुकी है, तो अब री-रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं क्या? My point is, Sir, for the last three months, my State is burning, both sides, Andhra and Telangana. Boys are committing suicide. Their parents are worried. We are all worried. What is happening in my State which is a progressive State marching forward? You are punishing such a State. What sin have my people in Andhra Pradesh committed?

Why are you dealing with such a sensitive issue in a casual manner? Mr. Prime Minister, I do agree that a State cannot be formed within six months or a year; in one meeting or two meetings but you have sufficiently taken time. You had an alliance with one of the parties. You made a promise to the people, and, now you have a direct discussion. You did not do homework, Sir. I don't know whether the people are properly briefing the hon. Prime Minister or not. The Chief Minister of Andhra Pradesh has gone on record saying that he was not taken into confidence. Many Ministers are expressing ignorance. Our colleagues, Members of

Parliament, have not been taken into confidence before a decision was made. They should have been taken into confidence. They are also Members of Parliament. I am answerable to my supporters. They are answerable to their supporters. The Chief Minister along with the Members of Parliament of both the regions, namely, Andhra and Telangana, should have been called separately. You should have held enough consultations with them and you should have prepared your mind before making an announcement. Now, you are doing it, I am told. Sir, is it the way to deal with such a sensitive matter relating to the future of a State. Sir, regional feelings become very strong. In this country, unfortunately, we are all aware that water, land, religion, region and language ignite emotions overnight. Moreover, Sir, the issue of Telangana has got a background. It is not an all of a sudden movement by somebody. Whoever is leading the movement, if they think that they are leading the movement, they are mistaken. Sir, it is the people's movement. Even on the other side, it is the people's movement. It is not correct to ridicule anybody. We may not agree with the viewpoint of the other person but to ridicule them and to say that it is all conspired, inspired or transpired by somebody is unfair. Sir, my point is that hundreds of students are ruining their lives. Examinations are coming nearer. On the one side, they have examinations, and, on the other, this tension is there in their minds. How do you expect them to perform better in the examinations? Sir, the regional feelings are growing up everybody. The national media is not able to properly understand and highlight as to what exactly is happening in that part of the country. There the entire State is worried, the investment has stopped, the growth has come to a halt, and, the division in different parties is increasing day-by-day. The ruling party has a division; the main Opposition party has a division. The division is bound to be there on this emotive issue. But, at the same time, should we allow this to continue? Do you want to spend one more year like this? What is the Srikrishna Committee for? Sir, I will accept, and, then, cooperate with the Government because the hon. Home Minister made a statement that responsible parties will talk to the Srikrishna Committee. That means he wants to imply that people who would not go to Srikrishna Commission, are irresponsible people. I would like to know from him whether this is the responsible way to go for such a unilateral announcement by the Union Home Minister to make such a Committee without understanding the implications. I would like to know this from the

hon. Prime Minister. If he gives an assurance, I will change my stand. Is the Srikrishna Committee's recommendation going to be binding on the Government of India? Is it going to be the end of this issue? Let him say. We will review our stand. If it is going to be just another committee like Pranab Babu Committee, or, Rosaiah Committee etc., what is its use? Why do you deceive people? Why are you deceptive in your approach? Be bold, be open. Sometimes, harsh decisions have to be taken. There is a background of Telangana agitation of 1969 or the Andhra agitation of 1972. Now, we have this agitation. Do you want this agitation to be precipitated leading to further increase in misunderstandings? I am really aghast and pained to see how these things are happening. People go on speaking to remove the word 'Andhra' from 'Andhra Bank'. There is some problem. We are pained to see when somebody drives away his neighbour from this region or place. So, I would like to request the hon. Prime Minister to please pay some personal attention to this, have a serious discussion within your party, and, come to a political conclusion. Don't leave it to a Committee. It is a time-pass Committee. I have made it very clear that we have no intention to cast aspersions on the ability of the Members who are there. We have nothing personal against them. We may greet them. Somebody said, why can't you meet them. Sir, we can meet them, we can greet them. But, what is the purpose; that is the issue. We meet Congressmen here. After we go out, I meet the Congress friends outside also. Dr. Keshava Rao is there. I can meet him, greet him also. Mr. Anand Sharma is here. I can greet him. Hariprasad ji is here, I can greet him. But is it the end of the story? The issue is that you need to be clear about the purpose of this Committee. ■

सारांश

देश माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण से निराश है, क्योंकि इसमें देश को पेश आ रही चुनौतियों का कोई उत्तर शामिल नहीं है। अभिभाषण में कुछ वायदों को पुनः दोहराया गया है। महंगाई सहित अनेक समस्याएं विद्यमान हैं। वास्तव में सरकार के पास कोई निदान नहीं है। किसी भी माननीय मंत्री ने महंगाई के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। यह सरकार कोई कार्यवाही करने में विफल रही है। महंगाई से आम जनता त्रस्त है। एक ओर,

राष्ट्रपतिजी के अभिभाषण के अनुसार खरीद शक्ति में बढोतरी हुई है और दूसरी ओर एनएसएसओ इस बात का खण्डन करता है। 'संप्रग' सरकार ने सशक्त अर्थव्यवस्था विरासत में प्राप्त की थी।

महंगाई का एक मुख्य कारण अनाजों के आयात और निर्यात में व्याप्त भ्रष्टाचार है। आपने सस्ते मूल्यों पर निर्यात किया और अधिक मूल्यों पर आयात किया। आपके पास उन फसलों या अनाजों पर अधिक जोर देने का पर्याप्त समय था जिनकी कमी थी। परन्तु आपने ऐसा नहीं किया। आप बहाने बना रहे हैं। हमारे शासन के दौरान आपदाएं आयी थी। हमने विभिन्न राज्यों को लगभग 40-60 लाख टन अनाज जारी किया था। आपने बाजार में खाद्यान्न जारी नहीं किए हैं। चीनी सहित अनाजों के निर्यात और आयात संबंधी घोटालों की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाना चाहिए। आपने देश में चीनी और चावल की कमी के बावजूद उनके निर्यात के आदेश दिए। अचानक मूल्यवृद्धि का क्या कारण है? हमें इस संबंध में बहस करनी चाहिए। जब हम सत्ता में थे तो मूल्यों को नियंत्रित करने में सफल रहे थे। आप एक-दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। आप सभी इसके लिए समान रूप से उत्तरदायी हैं। इस संबंध में कांग्रेस नेतृत्व भी मौन है।

भारत का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आज एशिया प्रशांत के सभी देशों में सबसे अधिक है। भारत में मूल्य वृद्धि का मुद्दा ही आज देश का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। कीमतों को रोकने के लिए क्या किया गया है? इसके बाद वित्त मंत्री जी ने बजट में यह घोषणा कर दी कि पेट्रोलियम की कीमतों में वृद्धि की जाएगी। सत्ताधारी दल का समर्थन करने वाले हमारे मित्र भी मूल्य वृद्धि को लेकर चिंतित हैं। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि का परिवहन शुल्क, सब्जियों, दूध, दाल, तेल, कोयला, स्टील इत्यादि पर असर पड़ेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार बजट सत्र के समाप्त होने के बाद एक बार फिर पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत में वृद्धि करने का इरादा रखती है।

हमारी मांग है कि एक संयुक्त संसदीय समिति गठित की जानी चाहिए जो यह पता लगाए कि गत वर्ष भारी फसल होने के बावजूद, जैसा कि मंत्री जी ने बताया है कि खाद्य पदार्थों की कीमतें क्यों बढ़ी हैं और वर्ष 2008-09 में 49 लाख टन चीनी 12.50 रुपये के हिसाब से क्यों निर्यात की गयी थी और इस समय 36-40 रुपये के हिसाब से क्यों आयात की जा रही है।

सरकार का यह दावा है कि उसने आतंकवाद की चुनौतियों का सामना

करने के लिए उससे उत्पन्न स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु नये उपाय किए हैं। यदि ऐसा है, तो पुणे की घटना क्यों घटी है? महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त की गयी राम प्रधान समिति ने एक रिपोर्ट में कहा था कि पुणे संभावित लक्ष्य हो सकता है। आज इस स्थिति के विषय में क्या कहेंगे? देश में आसूचना सुरक्षा अभी भी नाजुक स्थिति में है। राज्यों को जो भी परामर्शी नोट भेजे जाते हैं, वे बहुत सामान्य होते हैं। ऐसे सामान्य परामर्शों पर लोग अधिक ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा लगता है कि सरकार की इतनी ही नीति है कि 'मृतकों के प्रति संवेदना और जीवितों के लिए मुआवजा'।

पाक प्रायोजित आतंकवाद ने सरकार को कुछ सीमा तक मुद्दे की गंभीरता का अहसास कराया है। उन्होंने कुछ उपचारी उपाय करने शुरू किए थे, लेकिन आगे उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। सत्ताधारी दल के वरिष्ठ नेता खुले आम ऐसे दावों की पुष्टि कर रहे हैं कि बाटला हाउस पर पुलिस की कार्रवाई एक फर्जी मुठभेड़ थी। आतंकवादियों से लड़ते हुए जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, यह उन लोगों की स्मृति के प्रति घोर अन्याय है।

जहां तक देश की सुरक्षा का संबंध है, हम आपके साथ हैं और विपक्षी दल से जैसी भी सहायता की आवश्यकता हो, हम वह देने को तैयार हैं। सरकार को आतंकवाद से निपटने के लिए स्पष्ट नीति बनानी चाहिए। आतंकवाद से लड़ने के मुद्दे के साथ राजनीति और धर्म को जोड़ा नहीं जाना चाहिए। आतंकवादियों के साथ सख्ती से निपटना चाहिए।

नक्सलवादी पशुपति से तिरुपति तक 'रेड कौरिडॉर' चाहते हैं। उन्होंने अपना यह लक्ष्य बताया है। वे लोगों पर हमला कर रहे हैं और राष्ट्र की संपत्ति नष्ट कर रहे हैं। सरकार का यह कर्तव्य है कि वह माओवादी नेताओं के प्रति किसी प्रकार की नरमी न दिखाए। गैर सरकारी संगठन तथाकथित सिविल अधिकारों की बात करते हैं। वे किसके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं? ऐसे संगठित लोगों की तुलना में, जिनकी विचारधारा भिन्न और घातक है, आम आदमी अधिक महत्वपूर्ण है। सरकार को उनके साथ कोई बात नहीं करनी चाहिए।

यदि माओवादियों और सीपीआई-एमएल को अपनी विचारधारा में विश्वास है, तो उन्हें हथियार छोड़ देने चाहिए, राजनीतिक दल बनाना चाहिए और चुनाव लड़ कर सत्ता हथिया लेनी चाहिए। स्थिति दिन-प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। आज देश के कुल जिलों में से लगभग 25 प्रतिशत जिलों में माओवादी उपस्थित हैं। यदि स्थिति ऐसी ही रही, तो हमें आने वाले वर्षों

में कुछ जिले सेना को सौंपने पड़ेंगे। राज्य सरकारें अकेले इस समस्या से नहीं निपट सकती। भारतीय भूमि का 40,000 वर्ग किलोमीटर इलाका हमारे प्रशासन के अधीन नहीं है। क्या यह हम सबके सामने एक चुनौती नहीं है? इस संकट के विषय में लोगों को शिक्षित करने के लिए एक राजनीतिक शिक्षा कार्य योजना होनी चाहिए और उन लोगों को अलग-थलग कर दिया जाना चाहिए। कानून को भी साथ-साथ अपना काम करते रहना चाहिए। लोकतंत्र में उनसे बातचीत करने में कोई खराबी नहीं है, लेकिन उन्हें हिंसा और हथियारों का सशपथ त्याग करना चाहिए। सभी राजनीतिक दल कई वर्षों से समस्याओं को सुलझाने में लगे हुए हैं, लेकिन वे यह सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम नहीं, अपितु वे ही सब कुछ कर रहे हैं। यह बात स्वीकार नहीं की जा सकती है।

आतंक और वार्ता साथ-साथ नहीं चल सकते। स्वयं प्रधान मंत्री जी ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को राष्ट्रनीति के एक साधन के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। आतंकवाद को रोकने के लिए हमारे पड़ोसियों ने कोई सार्थक कदम नहीं उठाए हैं। जो आतंकवादी इस समय पाक-अधिकृत कश्मीर में बसे हुए हैं, उन्हें बिना किसी जांच-पड़ताल के देश में वापस आने की अनुमति देना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसी संभावना है कि समर्पण की आड़ में उग्रवादियों को भारत में भेजने की रणनीति अपनाई जाए। बेहतर होगा कि यदि इस संबंध में पहले सबके साथ चर्चा की जाए और तब आगे बढ़ा जाए। सरकार को लोगों के दिमाग से ऐसे हर संदेह को दूर करने के लिए स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिए।

शर्म-अल-शेख वक्तव्य से पता चलता है कि इस सरकार में कोई समन्वय नहीं है। विदेश राज्य मंत्री को बोलते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें भली प्रकार से परामर्श दिया जाना चाहिए और उनका मार्गदर्शन किया जाना चाहिए।

जहां तक तेलंगाना मुद्दे की बात है, पिछले तीन महीनों से वह राज्य जल रहा है। वहां पर लड़के आत्महत्या कर रहे हैं और उनके माता-पिता चिंतित हैं। हमें ऐसे गंभीर मुद्दे को हल्के रूप में नहीं लेना चाहिए। सरकार ने इस मामले में पर्याप्त समय लिया है और लोगों से वायदा किया है। निर्णय लेने से पहले सांसदों को विश्वास में नहीं लिया गया। घोषणा करने से पहले मुख्यमंत्री तथा आंध्र और तेलंगाना क्षेत्रों के सांसदों को अलग से बुलाकर उनके साथ पर्याप्त परामर्श किया जाना चाहिए था। क्षेत्रीय भावनाएं बहुत

शक्तिशाली हो जाती हैं। तेलंगाना के मसले की एक पृष्ठभूमि है। यह किसी के द्वारा अचानक चलाया जाने वाला कोई आंदोलन नहीं है, अपितु यह लोगों का आंदोलन है। समूचा राज्य इस विषय में चिंतित है, निवेश बंद हो गया है, वहां का विकास रूक गया है और विभिन्न दलों में मतभेद दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति को जारी नहीं रहने देना चाहिए। क्या श्रीकृष्ण समिति की सिफारिश भारत सरकार के लिए बाध्यकारी होगी? क्या इसके बाद इस मसले का अंत हो जाएगा? उस समय हम अपनी स्थिति की समीक्षा करेंगे क्योंकि मुद्दा यह है कि इस समिति का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को इस मुद्दे पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए, अपने दल के भीतर इस विषय पर गंभीर चर्चा करनी चाहिए और इसका राजनीतिक हल निकालना चाहिए।

जहां तक खाद्य सुरक्षा का संबंध है, पिछले वर्ष भी आपने कहा था कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम आ रहा है। अधिनियम क्या है? बजट में इसके लिए क्या प्रावधान किया गया है? केवल विधान बना देने से ही खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी, आपको और अधिक पारदर्शी ढंग से काम करने की जरूरत है। यूरिया की कीमतों में वृद्धि को वापस लिया जाना चाहिए। कृषि उत्पादन, बढ़ती हुई मांग के साथ गति बनाए रखने में विफल रहा है और सरकार द्वारा इसमें सुधार लाने के लिए बहुत कम काम किया गया है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में किसानों के कल्याण के लिए किए गए कई उपायों का बखान किया गया है। आपने एमएसपी में कई गुणा वृद्धि कर दी है। किंतु साथ ही निविष्टि की कीमतों में भी कई गुणा वृद्धि हो गई है। किसान को क्या लाभ मिल रहा है? हमारे किसान और ज्यादा उत्पादन करने के लिए तैयार हैं, आप उन्हें नई प्रौद्योगिकी दीजिए, आवश्यक सहायता दीजिए, वे ऋण लेते हैं। किसान व्यथित हैं और ऋण की वापसी अदायगी न कर पाने के कारण वे आत्महत्या कर रहे हैं। ग्रामीण लोग परेशान हैं क्योंकि पानी का स्तर गिरता जा रहा है। बिजली की स्थिति दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है। मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करें कि देश की प्रगति के लिए विद्युत क्षेत्र में सुधारों के लिए शीघ्र से शीघ्र कुछ सार्थक कदम उठाये जाएं।

संस्थाओं की बात करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रजातंत्र में संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। हाल ही में सरकार और सत्ता पक्ष द्वारा मितव्ययता उपायों के बारे में एक घोषणा की

गई थी। सरकार विज्ञापनों पर भारी राशि खर्च कर रही है। हमें गंभीर सोच रखते हुए इसके लिए कुछ करना चाहिए। अब मैं आस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय लोगों के विशाल समुदाय के मुद्दे पर आता हूं। उन्हें परेशान किया जा रहा है और कभी-कभी उनकी हत्या भी कर दी जाती है। इसलिए सरकार को इस मामले में अति संवेदनशील होने की जरूरत है और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रकार के कारगर कदम उठाने चाहिए कि उनका वहां पर ध्यान रखा जाए। श्रीलंका के तमिलों के बारे में बात करते हुए मुझे खेद है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, आज भी लगभग एक लाख लोग शिविरों में रह रहे हैं। शिविरों में उनकी हालत भयावह है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसका एक राजनीतिक हल निकाला जाए।

धर्म के आधार पर आरक्षण के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि आप ऐसा मत कीजिए। यह देश के हित में नहीं है। जहां तक राष्ट्रीय राजमार्गों का सवाल है, आवंटन में 13 प्रतिशत की कमी हुई है। आप लक्ष्यों को हासिल करने में विफल रहे हैं। पद्म पुरस्कारों के संबंध में मेरा कहना है कि उनका महत्व कम नहीं किया जाना चाहिए। देश से बाहर पड़े काले धन के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि स्विस् बैंक के खातों में अवैध रूप से पड़े हुए धन के संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है। बालिकाओं के लिए कुछ विशेष नहीं किया गया है। उनका और लोगों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। मैं भारत सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि 'सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोग्राम' की योजना को राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वित किया जाए। राज्यों को सहायता देने की बात पर आते हुए मेरा कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री ने बाढ़ के बाद आंध्रप्रदेश के लिए एक हजार करोड़ रूपए का वचन दिया था। किंतु वह राशि अभी तक पूरी तरह जारी नहीं की गई है। कर्नाटक सरकार को भी केन्द्रीय सहायता की जरूरत है। अब मैं महिला आरक्षण विधेयक की बात करता हूं। यह बेहतर होगा कि यदि यह पारित कर दिया जाता है। अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि देश के समक्ष चुनौतियां हैं और उनके लिए कोई समाधान होना चाहिए।■

तथ्यों से परे राष्ट्रपति अभिभाषण

& 'kkUrK dękj

मान्यवर उपसभाध्यक्ष जी, राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में अंतिम पृष्ठ की जो पंक्ति है, जिनकी चर्चा मेरे कुछ और मित्रों ने भी की है, वह मुझे सबसे अधिक अच्छी लगी। उन पंक्तियों में आज से लगभग 63 वर्ष पूर्व, 14 अगस्त 1947 को पंडित जवाहर लाल नेहरू जी द्वारा कहे गए शब्दों को उद्धृत किया गया है। वह एक संकल्प है देश से गरीबी दूर करने का, अज्ञानता दूर करने का और बराबरी लाने का। उस संकल्प को फिर से याद किया गया। मैं सबसे पहले उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। अभिभाषण में बहुत-सी बातों का जिक्र है, उपलब्धियों का जिक्र है। कुछ बातें सराहनीय हैं। जनता को उसका लाभ हुआ है, हो रहा है। मैं उन सराहनीय जनहित की बातों के लिए उनकी सराहना करता हूँ, समर्थन करता हूँ। लेकिन, मुख्य बात क्या है? जो मूल समस्याएँ देश की हैं और 63 वर्ष पहले जिन बातों के लिए संकल्प किया गया था, उन बातों के संबंध में क्या हुआ है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या गरीबी दूर हुई है? क्या विषमता दूर हुई है? क्या महँगाई की मार से गरीब बच रहा है? क्या आतंकवाद और माओवाद से किसी प्रकार की मुक्ति देश को मिली है? ये जो बुनियादी समस्याएँ हैं, इन पर क्या हुआ? यह है कसौटी सफलता की और विफलता की। बाकी बहुत-सी बातों की चर्चा है। आखिर संसद ने सरकार को 10 लाख करोड़ रुपये दिये थे। इतना पैसा दिया था तो खर्च तो होना ही था। Routine के कामों की चर्चा के बारे में पढ़ कर ऐसा लगता है कि जैसे वह सरकार का विज्ञापन हो। इतने करोड़ यहाँ खर्च किया, इतने करोड़ वहाँ खर्च किया। वह routine के कामों की चर्चा है, कोई बहुत बड़ी उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं है। कोई और सरकार होती, वह भी यह करती, लेकिन संकल्प का क्या हुआ? बुनियादी समस्याओं का क्या हुआ? प्रश्न यह है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, उस दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो आज गरीबी की दिशा में कुछ नहीं हुआ, यही नहीं है, बल्कि देश की गरीबी बढ़

रही है। आज 28 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं और इसी सरकार के विभिन्न विभागों ने 14 रुपए दैनिक की रेखा निश्चित की है, अर्थात् एक दिन में 14 रुपए में 28 करोड़ लोग जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं। कहां है आपका संकल्प? कहां है गांधी जी का अंत्योदय? 28 करोड़ लोग यदि गरीबी की रेखा से नीचे हैं और Global Hunger Index में जो भूख से पीड़ित देश हैं, उनमें भारत की गणना 68वें स्थान पर है। United Nations Food Programme के अंदर कहा गया कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा भूखे लोग आज भारत में रहते हैं, कुपोषण से सबसे ज्यादा बच्चे भारत में मरते हैं। मैं देख रहा था कि गरीबी दूर करने की दिशा में क्या उपलब्धि है? सच्चाई तो यह है कि गरीबी बढ़ी है और पिछले अधिवेशन में लोक सभा में सरकार ने स्वयं स्वीकार किया था कि गरीबों की संख्या 4 करोड़ 40 लाख बढ़ी है। उपसभाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि पिछले एक साल में एक भी व्यक्ति गरीबी की रेखा को पार करके ऊपर नहीं गया, तो फिर कहां है आपका संकल्प? 10 लाख करोड़ रुपया संसद ने आपको दिया, गरीबी दूर करने का संकल्प आपका था, लेकिन गरीबों की संख्या बढ़ी, एक भी व्यक्ति गरीबी की रेखा से उठकर ऊपर नहीं गया। इतना ही नहीं, अमीरी बढ़ गई। मेरे कुछ और मित्रों ने भी जिक्र किया है कि आज दुनिया में करोड़पतियों की संख्या में भारत के करोड़पतियों की संख्या बढ़ रही है। भारत के 100 अमीर लोगों की सम्पत्ति पिछले एक साल में 6 लाख करोड़ से बढ़कर 13 लाख करोड़ रुपए हो गई। 36 अमीर घरानों के पास 10 लाख करोड़ रुपए हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में अमरीका के पांच हैं तो भारत के तीन हैं। देश अमीर हो रहा है और देश गरीब हो रहा है। कुछ लोग इतने ज्यादा अमीर हो रहे हैं कि बहुत से लोग बहुत ज्यादा गरीब हो रहे हैं। यह दुर्भाग्य है देश का। यह एक चमत्कार है कि GDP बढ़ रहा है, अमीरी बढ़ रही है, लेकिन 28 करोड़ लोग झोपड़ियों में सिसक रहे हैं! यह स्थिति इस देश की है। कारण क्या है? सामाजिक न्याय नहीं हुआ। देश की सम्पत्ति बढ़ी, देश का ऐश्वर्य बढ़ा, GDP बढ़ा, लेकिन वह कुछ हाथों में ही सिमटकर रह गया और बहुत से लोग गरीब हो गए। उपसभाध्यक्ष जी, मैं समझता हूँ कि यदि यही गति सरकार की रही, यदि इसी प्रकार से pro-rich policy, anti-poor policies आपकी रहीं, जिन्होंने कुछ लोगों को कमाई करने का नहीं, लूट का लाइसेंस दिया, तो भारत में गरीबों और भूखे-नंगों की संख्या बहुत बढ़ेगी। एक साल में 100 लोगों की सम्पत्ति 6 लाख करोड़ से बढ़कर 13 लाख करोड़ हो गई और आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, आप संकल्प दोहरा रहे हैं 63 साल पुराना! इन 100 अमीर लोगों की सम्पत्ति अगर 6 लाख करोड़ से बढ़कर 13 लाख करोड़ हुई तो कमाई से नहीं, लूट से हुई और लूट का लाइसेंस किसने दिया? आपने दिया। मुझे लगता है कि अगर नीतियां और

हालात यही रहे तो कुछ दिन बाद भारत में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है और वह चमत्कार यह होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति लोग हिन्दुस्तान में होंगे और दुनिया में सबसे ज्यादा भूखे-नंगे भी हिन्दुस्तान में होंगे। तब शायद गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड्स में आपका नाम आ जाए, तब कौन सा पुरस्कार इस सरकार को देना पड़ेगा। मैं कहना यह चाहता हूँ कि संविधान के अंदर आर्टिकल 39 में कहा था Article 39 (c) provides that the operation of economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment. सम्पत्ति का कंसन्ट्रेशन नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन 63 वर्ष पहले से लेकर आज तक सम्पत्ति का एकाधिकार हो रहा है, कंसन्ट्रेशन हो रहा है।

उपसभाध्यक्ष जी, जो गरीबी है और अमीर तथा गरीब के बीच की जो खाई है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संकट है। देश की संपत्ति बढ़ रही है, यह खुशी की बात है, लेकिन वह संपत्ति कुछ ही हाथों में केंद्रित हो रही है और करोड़ों लोग भूखे-नंगे झोंपड़ों में सिसक रहे हैं, यह खतरे की घंटी है, बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। आज इस देश में अपराध बढ़ रहा है, दिल्ली में सुबह-सुबह अखबार पढ़ने से डर लगता है। सरकार की नाक के नीचे कितने अपराध प्रतिदिन होते हैं। नक्सलवाद बढ़ रहा है, माओवाद बढ़ रहा है। इन अपराधों के बढ़ने के पीछे एक बड़ा कारण गरीबी है, एक बड़ा कारण आर्थिक विषमता है, क्योंकि अगर करोड़ों लोग निराश हैं, हताश हैं, बेरोजगार हैं, दो वक्त की सूखी रोटी उनको नहीं मिल रही है। किसी पिता की आंखों के सामने अगर उसके बच्चे रात को भूखे सोते हैं, तो वह मजबूर, हताश कहाँ जाएगा? वह अपराध के रास्ते पर जा सकता है, वह नक्सलवाद के रास्ते पर जा सकता है। मैं यहाँ उद्घृत करना चाहूँगा – 'Development Challenges in Extremist Affected Areas' इस संबंध में एक Report of an Expert Group to Planning Commission है, इस रिपोर्ट के अंदर दो-तीन जगह, उन विद्वान लोगों ने जो निष्कर्ष निकाला है, उसे मैं सदन के सामने रखना चाहूँगा। एक जगह उन्होंने कहा है कि: "India is, today, proudly proclaiming an above nine per cent growth rate and striving to achieve a double digit growth, but it is a matter of common observation that the inequalities between classes, between town and country, and between the upper caste and the under-privileged communities are increasing. That this has potential for tremendous unrest is recognised by all." उपसभाध्यक्ष जी, विकास हो रहा है, लेकिन भेदभाव बढ़ रहा है, विषमता भी बहुत अधिक बढ़ रही है। इसी रिपोर्ट में से मैं एक और बात quote करना चाहूँगा, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं और विचार करने योग्य हैं। "The Administration should not have waited for the Naxalite

movement. The Administration should not have waited for the Naxalite movement to remind it of its obligation towards the people in this matter. But at least now that the reminder has been given, it should begin rectifying its own deficiencies. It should be recognised that such a responsibility would lie upon the Indian State even if the Naxalites were not there, and even in regions where the Naxalite movement does not exist." इस रिपोर्ट के मुताबिक नक्सलवादी, माओवादी मूवमेंट का सबसे बड़ा कारण गरीबी है, सबसे बड़ा कारण विषमता है। यह किसने फैलाई? आपने गरीबी दूर करने का संकल्प किया था और आपने विषमता दूर करने का संकल्प किया था, 63 साल के बाद आज सरकार की रिपोर्ट यह कह रही है कि नक्सलवाद, माओवाद का सबसे बड़ा कारण है आर्थिक विषमता। इस रिपोर्ट के अंत में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है – "There is no denying that what goes in the name of 'Naxalism' is, to a large extent, a product of collective failure to assure to different segments of society their basic entitlements under the Constitution, and other protective legislation." उपसभाध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि उस संकल्प का क्या हुआ, यदि उस संकल्प को आपने पूरा किया होता, तो आज नक्सलवाद इस ढंग से न होता। यह जमीन किसने तैयार की, यह गरीबी की जमीन किसने तैयार की, इसमें भुखमरी की खाद किसने डाली? आज नक्सलवादी उसमें बीज लगाने के लिए आ गए, यदि वे न आते, तो कोई और आता। इसका सबसे बड़ा कारण आर्थिक विषमता है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। मेरे कुछ मित्रों ने एक और बात का जिक्र किया है, मैं भी उसका जिक्र करना चाहता हूँ कि इस पूरे अभिभाषण में बढ़ती हुई आबादी की समस्या के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है। आज global warming की बात की जा रही है। जनसंख्या बढ़ेगी, तो घर बनेंगे, तो सड़कें बनेंगी, तो गाड़ियां होंगी, तो भीड़-भड़क्का होगा, सब कुछ होगा, लेकिन जनसंख्या को रोकने की दृष्टि से कोई चिंता सरकार नहीं कर रही है, प्रति वर्ष लगभग 2 करोड़ लोग हमारी आबादी में बढ़ रहे हैं।

चीन के मुकाबले हमारा वृद्धि दर अधिक हो गया है। 2025 तक भारत की आबादी 140 करोड़ हो जाएगी। स्टेशन से लेकर सड़क तक और हर जगह इतनी भीड़-भड़क्का दिल्ली में हो रहा है, लेकिन सरकार बिल्कुल चिंतित नहीं है। मैं निवेदन करूँगा कि प्रधान मंत्री जी इस सवाल पर पहल करे। सभी राजनीतिक दलों को बुलाकर एक National Population Policy बनाइए। कहीं ऐसा तो नहीं, जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद कर लेता है, वैसे ही हम इस समस्या से अपनी आंखें बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक और महत्वपूर्ण बात का जिक्र करना

चाहता हूँ, जिसकी चर्चा इसमें कहीं पर नहीं है। आज भ्रष्टाचार कैंसर की तरह, महामारी की तरह इस देश को अंदर से खोखला कर रहा है। सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार की बन रही है। हर कदम पर भ्रष्टाचार है, लेकिन कोई चर्चा नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। क्या सरकार ने भ्रष्टाचार से समझौता कर लिया है या सरकार को भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देता है? समय सीमा के कारण मैं केवल उसका जिक्र मात्र करूंगा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि निचले स्तर पर 21 हजार करोड़ रुपए का लेन-देन यहां पर होता है, और तो छोड़िए, उपसभाध्यक्ष जी, बिजली के अंदर जिसका नियंत्रण सरकार का Electricity Board करता है, उसमें तीस परसेंट से ज्यादा बिजली चोरी होती है। जो लगभग 27 हजार करोड़ रुपए की है। इस तरह से इस देश के अंदर 27 हजार करोड़ रुपए की बिजली की चोरी होती है। Transparency International की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 180 देशों को भ्रष्ट माना गया है, उनमें भारत का नंबर 84 पर है। महाभ्रष्ट देशों की सूची में भारत आ गया है, जो कभी विश्व गुरु कहा जाता था, जो कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज उसको महाभ्रष्ट कहा है। उसके लिए सरकार serious नहीं है। भ्रष्टाचार दूर करने के लिए सरकार गंभीर नहीं है। बेनामी Transaction Prohibition Act 1988 में बना, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। काले धन का उपयोग सबसे अधिक इसी में हो रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सीबीआई न्यायालयों में 9,310 मामले पड़े हैं, दो हजार मामले दस साल पुराने हैं, 154 अनुमति के लिए सालों से पड़े हैं। अनुमति नहीं देते हैं। जो अनुमति नहीं देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अपराध को छिपाना भी एक अपराध है। भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। Corrupt Public Servant Forfeiture of Property Bill 1999 की Law Commission की सिफारिश है। इसको पास कराइए। महान्यायाधीश कह चुके हैं कि इसको पास कराइए। सरकार गंभीर नहीं है, आज तक इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हैरानी की बात है कि लोकपाल बनाने का बिल Administrative Reform Commission की सिफारिश पर 1968 में सबसे पहले लोक सभा में लाया गया। चालीस साल हो गए, लेकिन वह लटका पड़ा है। सरकार भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए बिल्कुल गंभीर नहीं है। लोकपाल बिल चालीस साल से लटका हुआ है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जिसका जवाब चाहूंगा, वह यह है कि सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने एक affidavit दिया है, दिया कि नहीं दिया, क्या तथ्य है, मैं जानना चाहूंगा? मेरी जानकारी के मुताबिक उसमें कहा है कि जर्मनी सरकार ने सूचना दी है कि लिक्वेंस्टाइन बैंक में भारत के लोगों के गुप्त खाते हैं। Affidavit में भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, लेकिन आखिर में कहा है कि उन्होंने शर्त लगाई थी कि आप

इस सूचना को सार्वजनिक नहीं करें। अगर यह affidavit दिया है, तो आपने शर्त क्यों मानी? बेईमानों का नाम छिपाने की शर्त क्यों मानी? अगर आप ईमानदार हैं, तो बेईमानों के नाम छिपाने की शर्त क्यों मानी और नाम न बताने की बात कही है, कार्रवाई करने की बात तो नहीं कही। मैं जानना चाहूंगा कि उसमें असलियत क्या है? एक विचित्र बात, मैंने जैसे कहा कि भ्रष्टाचार बहुत गंभीर कैंसर के रूप में देश में फैल रहा है और इसके लिए पूरी दुनिया चिंतित है। मुझे इस बात की खुशी है कि भारत ही चिंतित नहीं है, बल्कि United Nations भी चिंतित है। United Nations Convention Against Corruption 2003 में बनी। दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट ने चिंता प्रकट की और एक convention बनाई।

मैं इसके लिए United Nations को बधाई दूंगा और इसकी भूमिका की चार पंक्तियां, जो UN Secretary-General, Mr. Kofi A. Annan ने लिखी हैं, उनको पढ़ना चाहूंगा – "Corruption is an insidious plague that has a wide range of corrosive effects on societies. It undermines the democracy and the rule of law, leads to violations of human rights, distorts markets, erodes the quality of life and allows organised crime, terrorism and other threats to human security to flourish". और उसके अंत में कहा है कि यह जो convention है, 'It makes a major breakthrough by requiring Member States to return assets obtained through corruption to the country from which they were stolen'. इसका उद्देश्य यह है कि अगर एक देश से करप्शन के द्वारा सम्पत्ति दूसरे देश में जमा की गई है, तो उस देश को वह सम्पत्ति लौटानी होगी। लेकिन हैरानी की बात है और मैं सरकार की तरफ से उत्तर चाहूंगा कि 2003 में इस convention को स्वीकृत किया गया। 140 देशों ने हस्ताक्षर किए और 120 देशों ने उसको ratify कर दिया, लेकिन भारत ने आज तक उसको ratify नहीं किया। आपने क्यों ratify नहीं किया? अगर दुनिया के 120 देश हस्ताक्षर करने के बाद इस convention को ratify कर सकते हैं, तो आपने उसको तंजपलि क्यों नहीं किया? क्योंकि यह आम बात है और इस बात के बहुत से प्रमाण आ चुके हैं कि लगभग 60-65 लाख करोड़ रुपया केवल स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में जमा है। यह पैसा इस देश का है, गरीबों का है, जो 28 करोड़ लोग झोंपड़ियों में कराह रहे हैं, उनका पैसा है। लोगों ने यह पैसा बेईमानी से लिया और विदेशों में जमा कराया और दुनिया की सबसे बड़ी अदालत ने एक convention, एक तरीका अपनाया और महोदय, यह देखकर हैरानी हुई कि स्विट्ज़रलैंड ने इस पर sign भी कर दिए और स्विट्ज़रलैंड ने ratify भी कर दिया ! उसे नहीं करना चाहिए था। उसकी तो मौज हो रही है, दुनिया भर के बेईमान लोगों के पैसे पर वह

देश मौज कर रहा है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड ने signature भी कर दिए, ratify भी कर दिया और भारत सरकार ने 2005 में हस्ताक्षर किए थे, लेकिन आज तक इस convention को ratify नहीं किया है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों नहीं किया? इस बात का जवाब हम चाहते हैं। अगर दुनिया के 120 देश यह कर सकते हैं, तो भारत क्यों नहीं कर सकता? महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि करप्शन के कारण गरीबी बढ़ती है, गरीबी के कारण विषमता बढ़ती है और गरीबी व विषमता आज इस देश में अपराध, तनाव और नक्सलवाद का सबसे बड़ा कारण है। मैं इतना ही कहूँगा कि सरकार इन सारी बातों के बारे में गंभीर नहीं है। आपने पुराने संकल्प का जिक्र किया, इस देश में तो यह संकल्प पहले से ही है। मुझे याद है स्वामी विवेकानन्द ने सबसे पहले यह कहा था कि हिंदुस्तान के लोगों, इस देश के गांव का गरीब आपका देवता है। भूल जाओ, सभी देवी देवताओं को। जब तक भारत का प्रत्येक व्यक्ति भरपेट भोजन नहीं करता, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के गरीब आदमी की सेवा करो और उसे उन्होंने 'दरिद्रनारायण' कहा। फिर महात्मा गांधी ने अंत्योदय की बात कही और 63 साल पहले आपने यह संकल्प दोहराया, लेकिन आज देश की हालत क्या है? भ्रष्टाचार से देश टूट रहा है। गरीबी बढ़ रही है, महंगाई की मार से देश की हालत खराब है। आज इस सदन में उड़ीसा की बात कही गई। रोज़ खबरें आती हैं कि किस ढंग से भुखमरी से लोग मर रहे हैं। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि देश की सरकार इस बारे में गंभीरता से विचार करे। गरीबी और अमीरी रहेगी, भगवान भी उनको बराबर नहीं कर सकता, लेकिन अति गरीबी दूर होनी चाहिए। बुनियादी समस्याएं और दो वक्त की सूखी रोटी हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। शायद इसी बात को देखकर महात्मा गांधी जी ने अंत्योदय की बात कही थी।

जो अंत में है, जो सबसे गरीब है, उसका विचार सबसे ज्यादा करिए, लेकिन आज सरकार की नीतियां अंत्योदय के आधार पर नहीं चल रही हैं। ये चतव तपवी नीतियां हैं, जिससे गरीबी और बढ़ रही है और गरीबी बढ़ने के कारण देश में तनाव बढ़ रहा है, आतंकवाद बढ़ रहा है, नक्सलवाद बढ़ रहा है। यह जो नक्सल गलियारा है, यह गरीब गलियारा है। जहां-जहां गरीबी जितनी ज्यादा है, वहां-वहां नक्सलवाद उतना अधिक बढ़ रहा है। नक्सलवाद में दो प्रकार के लोग हैं – एक नेता हैं, जो उस मूवमेंट को चलाने वाले हैं, वे विचारधारा से प्रेरित हैं, लोकतंत्र में उनका भरोसा नहीं है, वे देश को तोड़ना चाहते हैं, बंदूक के सहारे काम करना चाहते हैं। नक्सलवाद का नेतृत्व करने वाले लोग अलग हैं, उनके साथ किसी किसम की कोई दया नहीं होनी चाहिए। मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि नक्सलवाद को मिटाने के लिए सरकार बहुत बड़ा प्रयत्न कर रही है, उसमें किसी प्रकार की ढिलाई

नहीं आनी चाहिए। पूरा देश उसके लिए सरकार के साथ है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, उनके पीछे जो गांव के गरीब लोग चल रहे हैं, वे सभी विचारधारा के कारण साथ नहीं हैं। उनको बरगलाया जा रहा है, उनको फुसलाया जा रहा है – गरीबी और बेरोजगारी के कारण – जो इस रिपोर्ट में कहा है। इसलिए जब तक सरकार उन कारणों को दूर करने की कोशिश नहीं करेगी, तब तक यह तनाव, यह नक्सल और आतंक की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। मैं जहां सरकार को बधाई दूँगा कि नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए आप जो प्रयत्न कर रहे हैं, उसमें कोई ढील नहीं आनी चाहिए, लेकिन जो इस रिपोर्ट में कहा है कि नक्सलवाद की भूमि जो इस देश के अंदर तैयार हुई, उस गरीबी और अति गरीबी को दूर करने के लिए युद्धस्तर पर काम होना चाहिए। आज वह नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर हो रहा होता तो एक साल के बाद आप कहते कि हम पांच करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर ले आए, लेकिन आपको यह कहना पड़ा कि 4 करोड़ 40 लाख लोग और ज्यादा गरीब हो गए। नक्सलवाद को दूर करने की जम्मेदारी इस सरकार की है। देश की गरीबी और विषमता एक बहुत बड़ा संकट है इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार युद्ध स्तर पर अति गरीबी को दूर करने के लिए कुछ नयी नीतियां बनाए और बेईमानी तथा भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए विदेशी धन वापस लाने का प्रयत्न करे। इस कन्वेंशन पर सिग्नेचर करे। स्विट्ज़रलैंड से पैसा वापस लाने का जो वायदा किया था – कुछ नहीं हुआ। इसमें भी केवल चलते हुए उसका जिक्र है। महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार आज यह कानून बनाए कि गैर कानूनी तरीके से विदेशी बैंकों में पैसा जमा कराना अपराध है – आज भी कानून है – उसमें यह करे कि अपराध है और उस अपराध के लिए 20 साल की सख्त सजा तय कर दे। अगर कोई ढिलाई देनी है तो उसमें 6 महीने का समय दे दे और कह दे कि 6 महीने के अंदर जो लोग स्वयं अपने धन की घोषणा कर देंगे, उनको रियायत दे दी जाएगी, उनका नाम गुप्त रखा जाएगा। सरकार के पास उनके नाम हैं, जिनके खाते विदेशों में हैं। उनके खिलाफ थोड़ी सी कार्यवाही शुरू कर दी जाए और 20 साल की सख्त कैद की घोषणा की जाए तो सरकार के दरवाजे पर उन सब बेईमान लोगों की लाइन लग जाएगी जिन्होंने देश का 60 लाख करोड़ रुपया लूटकर विदेशों में जमा कराया। हमने इतिहास पढ़ा है कि दुनिया के लुटेरे आए और हमें लूटा। इस बार तो हमें अपनों ने लूटा और उन अपनों की कहीं आप रक्षा तो नहीं कर रहे, कहीं आप उनको बचा तो नहीं रहे? इस पर आज तक क्यों सिग्नेचर नहीं किए? जर्मन सरकार ने जो आपको नाम दिए हैं – एफिडेविट में आपने कहा है – उनके खिलाफ आप कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे? ये बहुत बुनियादी समस्याएं हैं। कितने करोड़ किस काम पर लगाए – रूटीन के काम

कोई भी सरकार करती – लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जो बुनियादी सवाल था, जो संकल्प था, जिस संकल्प को आपने दोहराया था, उस दिशा में कोई काम नहीं हुआ है। गरीब त्रस्त है, गरीब निराश है, विषमता बढ़ रही है, भ्रष्टाचार कैसर की तरह देश को खोखला कर रहा है।

भ्रष्टाचार चिंता का विषय है, सबसे चिंता का विषय यह है कि भ्रष्टाचार से सरकार ने समझौता कर लिया है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकार गंभीर नहीं है, यह और भी चिंता का विषय है। अंत में, मैं देश के उन करोड़ों लोगों को ध्यान में रखकर एक बात कहना चाहता हूँ, वे दुखी हैं, निराश हैं, परेशान हैं। इस देश के गरीब लोगों ने बहुत बर्दाश्त किया है और झोंपड़ी में रहने वाला गरीब आदमी जब अपनी आंखों के सामने अपने भूखे बच्चों को देखता है और फिर देखता है कि कुछ लोग रातों-रात अमीर हो जाते हैं, उसके दिल पर क्या बीतती होगी ? हम उससे क्या उम्मीद कर रहे हैं, वह कब तक इंतजार करेगा ? उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी और देश के उन गरीबों को ध्यान में रखकर, मैं अपनी बात हिन्दी के एक कवि की चार पंक्तियों से समाप्त कर रहा हूँ। इन्हीं लोगों की इस अवस्था का जिक्र करते हुए हिन्दी के कवि नीरज ने कहा है :-

‘तन की हवस मन को गुनहवार बना देती है,
बाग के बाग को बीमार बना देती है, ,
भूखे पेटों को देश-भक्ति सिखाने वालों,
भूख झुन्सान को गद्दार बना देती है।’
आप अधिक इंतजार मत करवाइये।

■

Synopsis

The President’s Address contains a number of things as well as achievements. The people have been benefited and are being benefited. I appreciate for it. But there are lots of basic problems of this country. Poverty is increasing and what is your achievement to eradicate it? Even not a single person has come above the poverty line. Some people are very rich. There is no social justice. I would like to say that the concentration of property should not be allowed. Besides, the crimes are on increase in the country and one of the major factors behind this is economic inequality. The people are in distress. They are unemployed.

Naxalism and Maoism are spreading their wings. No mention has been made on the rising population of the country. Global warming is being talked about but when the population would increase, the number of houses, roads, vehicles etc. would also increase. The Government are not concerned to contain the population. I would like to say that the Prime Minister should take some initiative in this regard and formulate a National Population Policy.

Nothing has been said about corruption in the Address. It is the biggest problem and on account of this, today India has been included in the most corrupt countries of the world but the Government is not serious to end corruption in the country. The power is controlled by Electricity Board and even then theft of power of crores of rupees is taking place in the country.

Lokpal Bill is pending for forty years. United Nations is also concerned about the corruption and they had formed a convention in 2003. Its objective was that if any wealth from a country by way of corruption, is put in another country then it has to be returned by that country. 140 countries have signed on it and 120 countries have ratified it but India has not ratified it so far. It has been reported that about 60-65 lakh crores of rupees are stashed in Swiss Banks which has been earned by corrupt activities whereas the people in our country are dying from hunger. I want to know the reasons for which India has not signed on this convention.

Today, the polices of the Government are not being implemented on the basis of Antyodya. These polices are pro-rich. Government is making great efforts for eradicating Naxalism and there should not be any laxity in this. Poverty should be eradicated on war-footing. This is not being done at all. Government should formulate some new polices to eradicate poverty and it should make efforts to bring back money deposited by Indians in foreign banks for stopping dishonesty and corruption.

Government should make a law that illegally depositing money in foreign banks is a crime and it should make provision for 20 years of rigorous imprisonment for it. Government is not serious to root out corruption. ■